● वर्ष-3
● अंक-115
रायपुर, शुक्रवार
22 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› 1 जनवरी को घर लाएं तांबे....

साय मंत्रिमंडल का विस्तार आज

बृजमोहन, ओपी सहित नौ मंत्री लेंगे शपथ

रायपुर।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। कल यानी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से सीएम विष्णुदेव के नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बात का एलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद किया है। साय कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा। कुल 9 विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे।

सीएम विष्णुदेव साय ने आज यानी गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि नौ विधायकों को नए मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। बहुत जल्द ही विभागों का भी बंटवारा होगा। इसके बाद एक और कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।

ये विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, लखन देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े

सीएम समेत अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं- संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में सीएम समेत अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में साय कैबिनेट में तीन सदस्य हैं। इसमें मुख्यमंत्री साय और दो डिप्टी सीएम क्रमशः अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने राज्य में बीजेपी का सरकार बनने के बाद 13 दिसंबर को शपथ ली थी।

3 दिसंबर को राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी बीजेपी- 7 और 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस को हराकर राज्य की सत्ता में आई है। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे। भाजपा ने 90 सीटों में से 54 सीटें जीतीं थी जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई, जो साल 2018 विधानसभा चुनाव में जीती गई 68 सीटों से कम है।

दूरसंचार विधेयक 2023 रास से भी पास

लोकसभा के सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा की बैठक निर्धारित अवधि से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत गत चार दिसंबर को हुई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार 22 दिसंबर तक इसका संचालन होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि इस सत्र में कार्य उत्पादकता करीब 74 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा, ''इस सत्र में 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे 50 मिनट तक चलीं। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए। कुल 18 सरकारी विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए।'' बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित

लोकसभा की स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन पेश किए। देश में 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त कर नया कानून बनाने के लिए लाए गए दूरसंचार विधेयक, 2023 को संसद ने बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र बहुत कठिनाई वाले दौर में था लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में इसे वहां से बाहर लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र पर घोटालों की कालिख लगती थी लेकिन आज यह उदीयमान क्षेत्र बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के कारण दुनिया में सबसे तेज गति से 5जी यहां लागू किया गया और इसके लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया वह भारत में बने हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कई सुधारों को जारी रखा गया है और इसके द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है।

भारत में पारसी कितने खुश और अमीर हैं, मुसलमान के सवाल पर बोले मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। यूके स्थित फाइनेंशियल टाइम्स से धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए, मोदी ने भारत में पारसियों की आर्थिक सफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि दुनिया में कहीं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद, उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिला है, वे खुशी से और समृद्ध होकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है।

साहित्य रचना केवल स्वांत सुखाय नहीं, बहुजन हिताय होनी चाहिए: भागवत

भुवनेश्वर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने कहा कि भाषा लोगों के दिलों के साथ-साथ समाज को जोड़ने का प्रमुख साधन है. साहित्य की रचना केवल स्वांत सुखाय ना होकर बहुजन हिताय होनी चाहिए. भाषा का सम्मान समुचित उपयोग प्रयोग से ही होता है. केवल पुरस्कार, सम्मान देने भर से भाषा आगे नहीं बढ़ती.

भारतीय दर्शन संपूर्ण विश्व के हित में है. इसलिए वर्तमान में मार्गदर्शन के लिए समग्र विश्व भारत की ओर देख रहा है.

धर्म को लेकर लोगों के मन में भ्रांत धारणाएं बनी हुई है. उपासना पद्धति धर्म नहीं होती. लोगों की उपासना पद्धति अलग-अलग हो सकती है, मगर धर्म एक है जो चिरंतन शाश्वत सत्य है. अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. मोहन भागवत जी ने भारत की विभिन्न भाषाओं के 14 प्रतिष्ठित साहित्यकारों का सम्मानित किया.

सरसंघचालक जी ने कहा कि मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है कि प्राणी आहार, बिहार, निद्रा, मैथुन करता है और केवल अपने ही हित की बात सोचता है. जबकि मनुष्य अपना हित साधन करने के साथ-साथ समाज के हित का भी ध्यान रखता है. देश के अलग-अलग प्रांतों में प्रचलित भाषाओं पर कहा कि मातृभाषा के उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए. अपनी भाषा में जब तक हम संवाद और कामकाज नहीं करेंगे, तब तक हमारा हित नहीं होने वाला.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में मनुष्य एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें वह केवल अपने ही हित की बात सोचता है. आत्महीनता में डूबा हुआ समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता. समाज को जागृत करने के लिए साहित्य को प्रयास करना चाहिए. अब समय अनुकूल चल रहा है, ऐसे में साहित्यकारों का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है कि वह भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को लेकर लोगों के भ्रम को दूर करें और समाज को एक सूत्र में बांधने में अपने महती भूमिका निभाएं. भारत की विशिष्टता यही है कि हमारे देश में एकता की विविधता है. हमारे यहां एकता में विभिन्नता नहीं है, विविधता नहीं है, हमारी तो एकता की विविधता है. इस बात को समझने में लोग गलती कर बैठते हैं और अनेकता में एकता की बात करने लगते हैं. जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे एकता की विविधता ही हमारी संस्कृति की पहचान है.

सरसंघचालक जी ने कहा कि भारत की अवधारणा धर्म को लेकर बिल्कुल साफ है. धर्म समाज और पर्यावरण सभी को जुड़े रहने की ताकत देता है जो बिखरने ना दे, वही धर्म है. भारत के इतर अन्य लोग धर्म को रिलिजन बताते हैं. जबकि रिलिजन उपासना पद्धति का ही नाम है. इसी गड़बड़ी के कारण लोग धर्म को लेकर संदेह में रहते हैं. कार्यक्रम में धरणीधर नाथ सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित थे. अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र द्विवेदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

प्रमुख समाचार

भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में निवेश बढ़कर 124.7 मि. डॉलर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीपीआईआईटी स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल के अनुसार अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 2014 में सिर्फ एक से बढ़कर 2023 में 189 हो गई है। उन्होंने कहा कि 2023 में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में निवेश बढ़कर 124.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार लगभग 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2-3त्न अनुमानित है और उम्मीद है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के कार्यान्वयन के साथ, यह वर्ष तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है। अपेक्षित अर्थव्यवस्था का आंकड़ा हासिल करने में निजी क्षेत्र की भूमिका प्रमुख होगी। यह उम्मीद की जाती है कि निजी क्षेत्र उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान निर्माण, उपग्रह सेवाएं प्रदान करने और ग्राउंड सिस्टम के निर्माण में स्वतंत्र रूप से एंड-टू-एंड समाधान अपनाएगा।

नए वैरिएंट जेएन.1 के खतरे के बीच ऐसे रहें सतर्क

नई दिल्ली। देश-दुनिया की तरह दिल्ली-एनसीआर में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए राजधानी के सभी अस्पताल अलर्ट हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों से सभी जरूरी उपकरण की जानकारी मांगी है। साथ ही, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू की उपलब्धता बनाए रखने का आदेश दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के नए स्वरूप को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना के नए स्वरूप कोविड जेएन.1 का कोई केस नहीं आया है, लेकिन यह तेजी से फैलता है। हालांकि, किसी भी मरीज को गंभीर नहीं कर रहा। मरीजों में हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश में हुए व्यापक टीकाकरण के कारण लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है। इस कारण फिलहाल स्थिति गंभीर होने की संभावना नहीं है। जीटीबी अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अमितेश अग्रवाल ने बताया कि नए स्वरूप को लेकर अध्ययन शुरू हो गया है। देश में पहला मामला केरल में पाया गया। वह मरीज भी गंभीर नहीं था।

धीरज के गुप्त चैंबरों से जब्त किए गये थे 329 करोड़: अधिकारी

नई दिल्ली। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसरों से आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई 351 करोड़ रुपये की नकदी में से 329 करोड़ रुपये ओडिशा के छोटे शहरों में जर्जर इमारतों से बरामद किए गए थे। आयकर विभाग ने ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक शराब भट्टी के परिसर और कांग्रेस सांसद से जुड़ी अन्य संपत्तियों पर मैराथन तलाशी अभियान चलाया। 6 दिसंबर को शुरू हुआ ऑपरेशन एक सप्ताह से अधिक समय तक चला और तीन राज्यों के 10 जिलों में फैले 30 से अधिक परिसरों को कवर किया गया। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक आईटी अधिकारी मौजूद थे और जब्त नकदी की गिनती के लिए 40 से अधिक मशीनें तैनात की गईं थीं। आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बयान में यह भी कहा कि तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत पाए गए और जब्त कर लिए गए। अधिकारियों ने कहा कि समूह का व्यवसाय झारखंड में रांची स्थित एक परिवार द्वारा नियंत्रित है और परिवार के सदस्यों में से एक रांची में रहने वाला राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति भी है। धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं।

प्राग शहर में शख्स ने की सरेआम गोलीबारी, 10 की मौत

प्राग। चेक गणराज्य में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें तकरीबन 10 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया है। चेक पुलिस और शहर की बचाव सेवा ने गुरुवार को मामले की जानकारी दी। हालांकि पुलिस द्वारा प्राग शहर में गोलीबारी की परिस्थितियों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। प्राग के मेयर बोहुस्लाव स्वोबोडा ने कहा कि चार्ल्स विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। साथ ही चौराहे पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को सड़कों पर न आने की हिदायत दी गई है, साथ ही लोगों से घर के भीतर ही मौजूद रहने का आग्रह किया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए चेक के आंतरिक मंत्री विट राकुसन ने कहा कि घटनास्थल पर कोई दूसरा हमलावर मौजूद नहीं था, एक हमलावर को पुलिस कर्मियों द्वारा मार गिराया है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि वह पुलिस का सहयोग करें। प्राग की बचाव सेवा ने कहा कि हमलावर को मौत के घाट उतार दिया गया हैं। घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है,और नौ लोगों गंभीर रूप से घायल हैं।

सैन्य वाहन पर घात लगाकर आतंकी हमला, चार जवान शहीद

जम्मू। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके के सावनी क्षेत्र में वीरवार की शाम आतंकियों के घात लगाकर दो सैन्य वाहनों पर किए गए हमले में चार जवान बलिदान हो गए, जबकि तीन जवान घायल भी हुए हैं। दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे मुठभेड़ जारी है। घटना राजोरी-थन्नामंडी-सुरनकोट रोड पर सावनी इलाके में शाम करीब 3.45 बजे की है। बताते हैं कि डेरा गली से बफलियाज की ओर से 48 राष्ट्रीय राइफल्स के दो वाहन आ रहे थे। इनमें एक जिप्सी तथा दूसरा ट्रक था। राजोरी-थन्नामंडी-सुरनकोट रोड पर सावनी इलाके में पहले से घात लगाए आतंकियों ने सैन्य वाहन देखते ही पहले ग्रेनेड दागा। इससे दोनों वाहनों के रुकते ही आतंकियों ने चारों ओर से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की संख्या चार से छह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सैन्य वाहन से बफलियाज इलाके से जवानों को लाया जा रहा था जहां बुधवार रात से घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चल रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों से गिरफ्तारी को लेकर ईडी की शक्तियों पर होगा असर

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया है। एक बार फिर ईडी द्वारा बुलाए जाने के बाद भी केजरीवाल पेशी के लिए नहीं गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तारी के समय किसी आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में मौखिक रूप से सूचित करना पर्याप्त है। हालांकि, 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में देना होगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ही गिरफ्तारी को लेकर दिया एक आदेश इससे कुछ इतर था। दो फैसलों की खास बात यह है कि शीर्ष अदालत ने एक ही सवाल पर कानून की व्याख्या दो तरह से की है। दोनों ही मामलों में आरोपी को गिरफ्तारी के आधार का लिखित दस्तावेज मुहैया नहीं कराया गया। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि बिना लिखित प्रमाण के गिरफ्तारी शक्तियों का मनमाना और निरंकुश इस्तेमाल है। हालांकि, दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। शुक्रवार के फैसले में शीर्ष अदालत ने ईडी की शक्तियों की अहम व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय अगर आरोपी को मौखिक सूचना भी देता है तो इसे पर्याप्त माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी जानकारी मौखिक रूप से देने के बाद की गई कार्रवाई को मानमाना नहीं माना जाएगा।

हालांकि, 24 घंटे के भीतर आरोपी को ग्राउंड की लिखित प्रति मुहैया कराना अनिवार्य होगा। 15 दिसंबर को पारित इस फैसले के बाद तीन अक्तूबर का फैसला निष्प्रभावी हो गया है। अक्तूबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहती है तो गिरफ्तारी के बुनियादों की प्रति आरोपी को लिखित रूप में मुहैया कराना अनिवार्य शर्त होगी।

दरअसल, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने के लिए पीएमएलए कानून के तहत कार्रवाई करती है। इस कानून की धारा 19 के तहत ईडी को गिरफ्तारी के अधिकार दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आरोपी को ईडी जल्द से जल्द लिखित रूप से बताएगी कि किन आधारों पर उसे अरेस्ट किया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए शुक्रवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश शर्मा की पीठ ने कहा, जल्द से जल्द को यथाशीध्र या जितनी जल्दी संभव हो समझा जाए।

अदालत ने साफ किया कि यथाशीध्र का अर्थ देरी की न्यूनतम गुंजाइश है। कितना समय लग सकता है? इस पर भी शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने स्पष्ट व्याख्या की। पीठ ने कहा, उचित रूप से सुविधाजनक या जितना उचित रूप से अपेक्षित हो उतनी अवधि के भीतर ईडी को लिखित दस्तावेज आरोपी को मुहैया कराने होंगे।

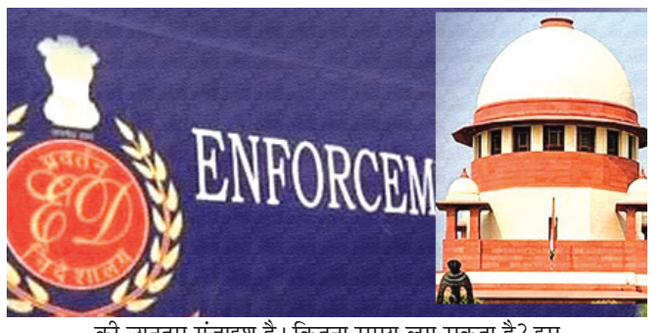

गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास कितनी ताकत?

दो दशक पहले बनाए गए कानून- धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए 2002) की धारा 19 ईडी को अधिकार देती है। इसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अधिकृत ईडी अधिकारियों को सबूतों या संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की ताकत मिलती है। इस धारा के तहत लगे आरोप के बाद ईडी भरोसा कर सकती है कि आरोपी ने इस कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है। कानून में स्पष्ट किया गया है कि ईडी को संदेह और गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। गिरफ्तारी के आधार के बारे में आरोपी को जितनी जल्दी हो सके जानकारी दी जाएगी। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को विशेष अदालत, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा।

दरअसल, 15 दिसंबर को जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पारित किया उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने रियल-एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के संस्थापक राम किशोर अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पंकज बंसल मामले में 3 अक्तूबर को पारित फैसला इस मामले में लागू नहीं होगा। आदेश पारित होने से पहले हुई गिरफ्तारी के खिलाफ राहत की अपील में इसे आधार नहीं बनाया जा सकता। बता दें कि अरोड़ा की गिरफ्तारी 26 जून को हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा, तीन अक्तूबर का फैसला दो- न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया। इससे पहले 27 जुलाई को विजय मंडनलाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला पारित किया। इस आधार पर तीन अक्तूबर का फैसला निष्प्रभावी किया जा सकता है। अरोड़ा ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19(1) और उनके अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दलीलों को खारिज करते हुए 15 दिसंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विजय मदनलाल के मामले में भी अदालत ने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार पर स्पष्ट टिप्पणी की है। इसमें भी कहा गया है कि मौखिक रूप से सूचित करना पर्याप्त है।

चौधरी के मामले में क्या है फैसला ?

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार, जस्टिस एएम खानविलकर (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने ईडी की शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या की थी। अदालत ने पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता बरकरार रखी थी। 27 जुलाई को कोर्ट ने 540 पेज का विस्तृत आदेश पारित किया। लगभग हर पहलू पर सरकार की दलीलों को स्वीकार कर शीर्ष अदालत ने कहा, पीएमएलए कानून की धारा 19 असंवैधानिक नहीं है। अदालत ने माना कि प्रावधान का पीएमएलए के उद्देश्य के साथ उचित संबंध है।

आज भारत बंद का ऐलान, नारायणपुर में नक्सली उत्पात, सड़क खोदकर गिराए पेड़

■ सोनपुर और कोहकामेटा में आवागमन ठप

नारायणपुर। 22 दिसंबर को नक्सलियों ने भारत बंद बुलाया है। लेकिन उससे पहले नक्सली काफी सक्रिय है। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में नक्सली उत्पात मचा रहे हैं। नारायणपुर में नक्सलियों ने फिर रोड जाम किया है। अबूझमाड़ सोनपुर और कुंदला कोहकामेटा मार्ग में नक्सलियों ने रोड जाम किया है।इसके लिए नक्सलियों ने सड़क खोदकर उसके आगे पेड़ काटकर गिराए हैं।जिससे दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई है।टू व्हीलर से लेकर यात्री बस और मालवाहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि सोनपुर मार्ग में लंबे समय के बाद नक्सली उत्पात देखने को मिला है।नक्सलियों ने नारायणपुर सोनपुर मार्ग के कोडोली गांव के पास पेड़ काटकर और सड़क को खोदकर आवागमन बाधित किया।वहीं

कुंदला से कोहकामेटा मार्ग के पुल के पास भी सड़क खोदा गया है। जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में आवाजाही प्रभावित होने से यात्री बस के पहिए भी थमे हैं।

बैनर पोस्टर के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश

नक्सलियों ने कई जगह मार्ग बाधित कर चेतावनी वाले बैनर पोस्टर भी चस्पा किए हैं।इन बैनर और पोस्टर्स में आसपास बम लगे होने की बात लिखी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों छोटेडोंगर के कोमल मांझी की हत्या की जिम्मेदारी भी नक्सलियों ने ली है। नक्सलियों ने कोमल मांझी पर आमदाई माइंस में पैसे खाने का आरोप लगाया था। इसी के साथ 22 दिसंबर को नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया है।

बीजापुर में भी नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। मद्देड़ के सोमनपल्ली में लगे टावर में आग लगा दी है। इलाके में बंद को लेकर बैनर- पोस्टर भी फेंके हैं। थाना प्रभारी रविशंकर साहू ने बताया कि टावर में लगे बेटरी बॉक्स में आगजनी की गई है। कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। इलाके में दहशत का माहौल है।

बीजापुर में मोबाइल टावर में लगाई आग

बीजापुर। 22 दिसंबर को भारत बंद से पहले नक्सलियों ने बीजापुर जिले में उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजापुर जिले के ग्राम मद्देड़ से करीब आठ किलोमीटर दूर सोमनपल्ली में लगे एक मोबाइल टावर को नक्सलियों ने बुधवार गुरुवार की दरमियान रात को आग के हवाले कर दिया है। साथ ही बंद को लेकर यहां पोस्टर पर्चे भी फेंके हैं। ज्ञात हो कि नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। खबर लिखे जाने तक घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी।

दंतेवाड़ा पुलिस का नक्सलियों पर नया एक्शन प्लान

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में नक्सली अब कहीं भी हो बच नहीं पाएंगे। नक्सलियों के सप्लाई

नेटवर्क को तोड़ने और स्माल एक्शन टीम पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी के तहत शहरों की तर्ज पर दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन सीसीटीवी के जरिए पुलिस को नक्सलियों को पकड़ना काफी आसान होगा। कई मामलों में सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस को अहम लीड भी मिल चुकी है। दंतेवाड़ा जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है। जहां आये दिन नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करने रेलवे पटरी उखाड़ने, सड़क निर्माण में लगे गाड़ियों में आगजनी, विकास कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं और फरार हो जाते हैं। ऐसे जगहों पर सीसीटीवी नहीं होने से नक्सलियों का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इससे निपटने पुलिस अब नक्सल प्रभावित एरिया में सीसीटीवी लगा रही है। इससे कम समय में पुलिस ऐसे नक्सलियों पर जल्द से जल्द एक्शन ले सकेगी। जिले में अब तक शहर के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिसे क्राइम के मामलों में पुलिस को बड़ी मदद मिलती रही है। लेकिन दूरस्थ और वनांचल में सीसीटीवी नहीं होने से पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। दंतेवाड़ा पुलिस और प्रशासन ने नक्सलियों पर लगाम लगाने शहर के साथ गीदम, बचेली, किरन्दुल, कुआकोण्डा, बारसूर, कटेकल्याण, अरनपुर में कैमरे लगाए हैं। इनके अलावा हिरोली, पोटाली, बोदली, कमारगुड़ा व अंदरूनी सुरक्षा बलों के कैंप और रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 चरणों में 512 कैमरे लगाने की योजना है।

अतिक्रमणकारियों के बेदखली की तैयारी

वन भूमि पर कब्जा करने वाले 30 लोगों को जारी हुआ नोटिस

गरियाबंद। उदंती सीतानदी अभ्यारण में अतिक्रमणकारियों पर एक और बड़ी बेदखली की कार्रवाई की तैयारी हो गई है। उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि अभ्यारण्य के बफर जोन में आने वाले तौरेंगा रेंज के टांगरान जंगल में 29 अतिक्रमणकारियों को बेदखली करने की कार्रवाई 3 जनवरी को किया जाना है। इसमें 25 ओडिशा नवरंगपुर जिले के रहवासी हैं। इनके खिलाफ जून में ही नोटिस जारी किया गया था। आरोपी कार्रवाई को अवैध बताते हुए न्यायालय के शरण तक भी गए। न्यायालय के निर्देश के बाद विभाग के आला अफसरों ने सुनवाई किया। 4 महीने की सुनवाई के बाद अभ्यारण्य प्रशासन ने कार्रवाई को जायज बताया गया। 13 दिसंबर को विभाग के उप सचिव द्वारा कार्रवाई को यथावत रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अभ्यारण प्रशासन की कार्रवाई को आरोपियों ने चुनौती देने अपने कब्जा को वैध बताया था। अपने दावा में 2005 से पहले काबिज और फर्जी तरीके से पाए गए वन अधिकार पट्टे का हवाला दिया था। सुनवाई के दौरान विभाग ने इसरो द्वारा जारी उस सेटलाइट इमेजरी को पेश किया जिसमें काबिज वाले स्थानों पर 2008 से लेकर 2011 तक जंगल नजर आ रहे थे। विभाग ने 2015 के बाद किए गए उस कार्रवाई का भी हवाला दिया जिसमें ताजा अतिक्रमण का सबूत मिटाने आरोपियों ने 265 पेड़ और 105 ठूठ को जलाने का प्रयास किया था।

जून महीने में वन अमला इचरादि में काबिज लोगों को बेदखल करने पहुंचा तो वहां के लोगों को टांगरान के अतिक्रमणकारियों ने भड़काकर वन अमले पर हमला करवाया था। इस हमले में कुछ कर्मी घायल हुए थे। सरकारी गाड़ी में भी टूट फूट हुई थी। आरोपियों का मकसद टांगरान पर होने वाली कार्रवाई को रोकना था। लेकिन उपनिदेशक वरुण जैन के ठोस इरादे के आगे इचरादी में विभाग पर भय बनाने की कोशिश नाकाम साबित हुई थी।

अब तक 600 हेक्टयर हो चुका खाली

कई राजनीतिक दबाव के बावजूद वरुण जैन बेदखली अभियान को जारी रखे हुए हैं। जनवरी में धमतरी के घोरा गांव को खाली कराने के बाद इंदागांव और तौरेंग रेंज में कार्रवाई जारी है। मई और जून महीने में सोरनामाल, गोहरामाल और इचरादी में 250 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को अभ्यारण्य के 600 हेक्टेयर जमीन से बेदखल किया। ये वन, पर्यावरण और वन्य प्राणियों के सुविधा के लिए कार्य किया जा रहा है।

सरगुजा संभाग में 13 हाथी दल सक्रिय, अलर्ट मोड पर वनविभाग

सीतापुर। छत्तीसगढ़ में हाथी झारखंड की सीमा से दाखिल होते हैं। इसके बाद मध्यप्रदेश की ओर चले जाते हैं।इस दौरान हाथी जशपुर,अंबिकापुर, बलरामपुर,कोरबा होते हुए कोरिया के रास्ते गौरेला पेंड्रा मरवाही में दाखिल होते हैं।जहां से मध्यप्रदेश के जंगलों की ओर चले जाते हैं। साल भर हाथी इसी रूट से आते जाते हैं।ऐसे में कई हाथी अपने दल से अलग भी हो जाते हैं।जो गांवों में घूमकर उत्पात मचाते हैं।इन दिनों सरगुजा में 40 से अधिक हाथी दल विचरण कर रहा है। जिसे लेकर ग्रामीण चिंतित हैं।

सरगुजा संभाग की यदि बात करें तो बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा जिला सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित है।अंबिकापुर जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में 22 हाथियों का दल विचरण कर रहा है।जिसमें उदयपुर वनपरिक्षेत्र के 9 हाथियों का समूह भी शामिल है। ये हाथी रायगढ़ जिले के कापू वन परिक्षेत्र से दिन ढलते ही मैनपाट वन परिक्षेत्र में पहुंच आते हैं। जिसके बाद बस्ती की ओर खलिहाल में रखे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में खंडराजा, परपटिया , सरभंजा और ढाडकेसरा शामिल हैं।जहां हांथी विचरण कर रहे हैं। यहां के लोग रात में अपने घरों से निकलकर कड़कड़ाती ठंड में अपने खेतों और घरों की रखवाली करते हैं।ताकि रात के समय में हाथी बस्ती की ओर ना घुसे।

ग्रामीणों की माने तो तब कभी भी वनविभाग की गाड़ी का सायरन बजता है तो गांव के लोग अलर्ट हो जाते हैं।सभी अपने घरों से निकलकर सड़क पर इकट्ठा होते हैं।इसके बाद सभी ग्रामीण पहरेदारी करना शुरु करते हैं।ताकि रात के अंधेरे में अनजान खतरा गांव में ना घुस आए।कुछ दिन पहले ही सरभंजा गांव में हाथी दल आ धमका था।जिसने

किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया था।

वनविभाग के अफसर हाथी मूवमेंट को लेकर हैं मुस्तैद

वहीं वन विभाग के अधिकारी हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वनविभाग की माने तो जिस ओर हाथी जाते हैं,उस ओर के गांव और बस्ती को अलर्ट किया जाता है।ज्यादातर लोगों को ये बताया जाता है कि घरों के सामने आग जलाकर रखें।

एसडीओ प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा हम हाथी के मूवमेंट पर सतत निगरानी रखते हैं। समय-समय पर लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि वह जंगल की ओर न जाए। साथ ही यह हाथी का दल रायगढ़ जिले के कापू वनपरिक्षेत्र से रात होते ही मैनपाट वन परिक्षेत्र में चले आते हैं।

सरगुजा संभाग में हाथियों का आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से हाथी किसानों की फसल को निशाना बना रहे हैं।कई लोगों के घर भी हाथी और मानव द्वंद की भेंट चढ़ गए हैं।सरगुजा संभाग सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित रहा है।यहां रहने वाले ग्रामीण हाथियों के कारण काफी ज्यादा नुकसान झेलते हैं।वनविभाग हर साल दावे तो करता है।लेकिन हाथी जब आते हैं तो सारी व्यवस्थाएं और दावे धरे के धरे रह जाते हैं।

दिनदहाड़े दुकान में घुसा भालू, दहशत में लोग

कांकेर। कांकेर के नरहरपुर नगर में भालुओं का खौफ बढ़ता जा रहा है। नगर में घूमने वाले भालू अब घरों व दुकानों में दिनदहाड़े घुसने लगे हैं। दुकान में घुसने का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें भालू को दुकान के अंदर घूमते देखा जा रहा है।

वीडियो 20 दिसंबर का बताया जा रहा है। शहर में फैमिली कलेक्शन के नाम से दुकान है। 20 दिसम्बर को शाम 4 बजे फर्म के संचालक वीरेंद्र जैन ने अपने वर्कर को दुकान के दूसरे कमरे में किसी समान के लिए भेजा। वर्करजैसे ही कमरे में घुसा उसने देखा कि अंदर भालू घूम रहा है। भालू को देखते ही वह तुरंत कमरे से निकल गया और अपने मालिक को कमरे में भालू होने के बात बताई। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए। संचालक वीरेंद्र जैन ने दुकान के दो साइड का शटर गिरवाया और पीछे का शटर खुलवाया गया। जिसके बाद भालू पीछे के दरवाजे से निकलते हुए बाड़ी से लगे खेत की ओर निकल गया। भालू के दुकान से जाने के बाद वहां मोजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

आए दिन नगर के अलग-अलग इलाकों में भालू को देखा जा रहा है। खाने की तलाश में

जंगल के ये जीव आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। पहले रात के अंधेरे में सूनी पड़ी दुकानों व घरों में घुसने वाले भालू अब दिनदहाड़े घुस रहे हैं।

गौरतलब हो कि कांकेर शहर में इन दिनों भालू का आतंक लगातार जारी है।आये दिन रहवासी इलाकों में भालु पहुंच रहे है। भालुओं की आमद से लोग दहशत में है।जिसे देखते हुए विभाग रात्रि गस्त की बात कहती है लेकिन कुछ दिन बाद फिर बंद कर देती है। कांकेर नगर के आस-पास शिवनगर-ठेलकाबोड के पहाड़ियों में 2014-2015 में 30 हजार हेक्टेयर भूमि में वन विभाग ने भालू विचरण और रहवास क्षेत्र बनाया था। जिसका नाम जामवंत परियोजना दिया गया था। इस परियोजना के तहत अमरूद,बेर,जामुन जैसे फलदार वृक्ष लगाना था। वन विभाग ने फलदार पौधा तो लगाए लेकिन कोई भी फल देने लायक नही बन पाया जिसके कारण अब जंगली भालुओं को शहर की तरफ भोजन के लिए आना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ में जल्द बंद हो सकती है मिड डे मील योजना!

कोरबा। छत्तीसगढ़ के सरकारी मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था चरमरा गई है। एक तरफ बच्चों को देने वाले आहार के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बच्चों को खाना बना कर देने वाले समूहों और रसोइयों को भी 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कई स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलने की सूचना है। जिन स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है वहां या प्रधान पाठक अपने जेब से पैसे लग रहे हैं या फिर महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं दुकानों से उधार सामान लेकर बच्चों के लिए स्कूल में खाना बना रही है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार से ही भुगतान जारी नहीं हुआ है। इसके कारण समूहों को पैसे जारी नहीं हुए हैं। समूह के अधीन काम करने वाले रसोइयों को मानदेय के रूप में हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से वो पैसे भी नहीं दिए गए हैं। जिसके कारण कुछ स्कूलों में सिर्फ दाल, चावल, अचार या चावल और सब्जी देकर बच्चों को मिड डे मील खिलाया जा रहा है।

पुलिस विभाग में सात साल की बच्ची की अनुकम्पा नियुक्ति

दुर्ग। दुर्ग पुलिस विभाग में महज सात वर्ष के बच्ची को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। बच्ची बाल आरक्षक के रुप में भर्ती की गई है। बच्ची के पिता की असामयिक निधन के बाद पुलिस विभाग ने एक बाद अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। बच्ची अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। जहां एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बच्ची को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रमाण पत्र सौंपे। दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने अंजली भट्ट को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त किया है। बच्ची के पिता अतुल भट्ट आरक्षक के पद पर दुर्ग जिले में पदस्थ थे। नौकरी के दौरान हार्ट अटैक से आकस्मिक मृत्यु के बाद एसएसपी द्वारा अनुकम्पा नियुक्त के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी सभी कार्रवाई जल्द पूरी करते हुए बच्ची को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के निर्देश दिए थे। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सात साल की अंजली भट्ट को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। अंजली 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा।

कोरिया में पश्चिमी विक्षोभ दे सकता है दस्तक

कोरिया। छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात अगर कोरिया जिले की करें तो सुबह और रात के समय तापमान में भारी गिरवाट देखने को मिलती है। पिछले तीन दिन से रात का तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गुरुवार को भी जिले का पारा 5 डिग्री पहुंच गया था। रेलवे स्टेशन बैकुंठपुर रोड पर कड़कड़ाती ठंड में यात्री गंतव्य की ओर जा रहे हैं। स्टेशन पर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ठंड के बीच यात्री ठिठुर रहे हैं। बात अगर कोरिया की करें तो सोमवार से जिले का पारा 6 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान भी 3 डिग्री से गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो तापमान में गिरावट का यह सिलसिला आगे भी बना रहेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है। जिलेभर में मौसम में आए बदलाव के कारण अब रात के साथ ही दिन में भी शीतलहर का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया है।

धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से हो रही ठगी

गौरेला पेंड्रा मरवाही। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों से समिति में ठगी का आरोप लगा है। खरीदी केंद्र के अधिकारियों पर आरोप है कि वो निर्धारित वजन से 1 किलो तक अधिक धान किसानों से वसूल रहे हैं। किसानों का कहनाा है कि 40 किलो तक लिया जाने वाला धान 41 किलो वजन में खरीदा जा रहा है। किसान जब धान तौलने वाले से शिकायत कर रहा है तो वजन करने वाले कर्मचारी सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। किसानों का कहना है कि कभी वो धान में नमी होने का बहाना बनाकर अधिक धान ले रहें हैं तो कभी कहते हैं कहा गया है प्रति बोरा धान 1 किलो तक ज्यादा लो। किसानों की शिकायत है कि अगर बोरे का भी वजन किया जाए तो वो 1 किलो नहीं होगा। तौलत किसान से जब इस शिकायत पर सवाल किया गया तो वो कुछ भी साफ साफ बोलने से बचता दिखा। किसानों का कहना है कि वो दूर से आते हैं अगर यहां बहस करेंगे तो उनका काम बिगड़ जाएगा। खरीदी केंद्र में जिस तरह की ठगी चल रही है उससे किसान दुखी हैं।

बस्तर में क्रिसमस की तैयारी लगभग पूरी, लोगों में उत्साह

बस्तर। पूरे विश्व में क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही बस्तर में भी क्रिसमस पर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। क्रिसमस को लेकर बस्तरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिसंबर माह के शुरुआती दिनों से लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। बस्तर संभाग के सबसे बड़े चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च को भी सजा दिया गया है। यहां दर्जनों लोग मिलकर चर्च को सजा रहे हैं। जिले में क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर मीडिया ने चर्च के सदस्य अनिल सेंट जॉन से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि, बस्तर संभाग का यह सबसे बड़ा चर्च है। इसकी स्थापना को लगभग 125 साल पूरे हो चुके हैं। सन 1898 में इस चर्च की स्थापना हुई थी। चर्च की इमारत साल 1933 में बना था। बस्तर संभाग के सबसे पुराने चर्च होने के कारण यह कलीसिया भी बड़ी है। इस चर्च में काफी संख्या में सदस्य भी हैं। चर्च बड़ी होने के कारण लोगों की सहभागिता भी सबसे अधिक होता है।

सनातन धर्म से दूसरे धर्म में शामिल हुए 101 परिवारों की होगी घर वापसी

कोरबा। धर्म सेना की ओर से कटघोरा के संस्कृतिक भवन में रविवार 24 दिसंबर को धर्मांतरण कर चुके परिवारों की घर वापसी कार्यक्रम रखा गया है। यहां समाज प्रमुख सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए 101 परिवारों की घर वापसी होगी। यानी कि ये वापस सनातन धर्म में शामिल होंगें।

दूसरे धर्म में गए हिंदू परिवारों की वापसी

शहर के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान धर्म सेना के बिलासपुर विभाग अध्यक्ष विष्णु पटेल ने घर वापसी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख और धर्म सेवा छत्तीसगढ़ के प्रदेश संरक्षक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और हिंदू वाहिनी के

राष्ट्रीय सह सचिव कौशलेंद्र सिंह की उपस्थिति में समारोह का आयोजन होगा। इसमें घर वापसी कार्यक्रम में हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए लोगों के पैर धोकर पूरे हिंदू रीति-रिवाज से उनकी घर वापसी कराई जाएगी। कार्यक्रम की पूरी तैयारी की जा चुकी है। वर्तमान में हिंदू धर्म के लगभग प्रत्येक समाज के लोग धर्मांतरण के जाल में फंसकर धर्मांतरित हो रहे हैं। इसलिए पहली बार कार्यक्रम के दौरान सभी जिले में रहनेवाले हिंदू समाज के दो-दो प्रमुख लोग भी आमंत्रित किए गए हैं। घर वापसी कार्यक्रम से जुड़कर हिंदू धर्म में परिवारों की वापसी के लिए अहम भूमिका निभाने वाले समाज प्रमुखों को सम्मानित किया जाएगा।

बहला-फुसलाकर कराया धर्म परिवर्तन

कोरबा जिले में हिंदूवादी 17 संगठन हैं। उन्हें भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिनका सम्मान किया जाएगा। इस बारे में धर्म सेना के प्रदेशध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पहले पिछड़े क्षेत्र के लोगों का ही धर्मांतरण हो रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में धर्मांतरण तेजी से बढ़ा और शहरी क्षेत्र में हिंदू धर्म के सभी समाज के लोग धर्मांतरण के शिकार होने लगे। धर्मांतरण की मुख्य वजह संबंधित धर्म के लोगों की ओर से प्रलोभन देना है। ऐसे परिवारों के हिंदू धर्म में वापसी के लिए घर वापसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

बता दें कि कोरबा में लगातार दूसरे धर्म में गए लोगों को समझा बुझाकर उनकी घर वापसी कराई जाएगी। कुल 101 परिवार वापस सनातन धर्म को अपनाएंगे।

अवैध रेत खनन को लेकर एक्शन मोड में विधायक रेणुका सिंह

भरतपुर-सोनहत। विधायक पद की शपथ लेने के बाद रेणुका सिंह एक्शन मोड पर आ गई हैं। भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा को निर्देश देने के बाद जिले के खनिज विभाग ने भरतपुर सोनहत विधानसभा में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रेत भंडारण पर रेत भंडारण करने वाले शिवम सिंह पर खनिज विभाग ने 2 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। भरतपुर विकासखंड के ग्राम बड़वाही में क्षमता से ज्यादा मात्रा में रेत भंडारण पर खनिज विभाग ने खनिज अधिनियम 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि रेणुका सिंह ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मेरे विधायक बनते ही इस क्षेत्र में अवैध रेत का कारोबार रुकेगा। रेणुका सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान यहां हो रहे अवैध रेत कारोबार को चुनावी मुद्दा बनाया था। उन्होंने क्षेत्रवासियों से यह वादा किया था

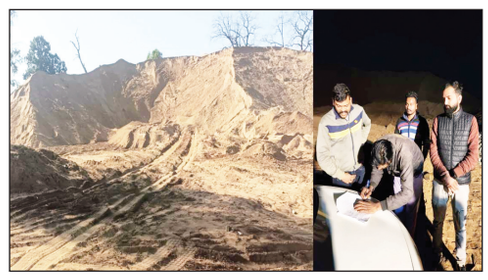

कि भाजपा सरकार और मेरे विधायक बनते ही यहां रेत का अवैध कारोबार रुकेगा। उन्होंने कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो जनता की इच्छाओं के विपरीत काम करे। उन्होंने तत्कालीन विधायक पर भी निशना साधते हुए कहा था कि जब वे विधायक नहीं थे तो कहते थे कि बालू नहीं ले जाने दूंगा। जब विधायक बन गए तो रेत माफिया के सबसे बड़े पार्टनर बन गए।

किसान आत्महत्या मुद्दे पर हंगामा, स्थगन प्रस्ताव पर अड़े विपक्ष ने किया वाकआउट

नियम प्रक्रियाओं से परे सदन नहीं चल सकता, स्थगन का उल्लेख नहीं किया गया है - बृजमोहन, यह अनुपूरक बजट मोदी की गारंटी का बजट है- चंद्राकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही के शुरुआत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी और डा रामलाल भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दो मिनट का मौनकर रखकर सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले किसान आत्महत्या पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले नारायणपुर के किसान आत्महत्या मुद्दे पर चर्चा की मांग की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सदन में कहा, विशेष परिस्थिति है, किसान ने कर्ज के बोझ से आत्महत्या की है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसपर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, नियम प्रक्रियाओं से परे सदन नहीं चल सकता, स्थगन का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए चर्चा उचित नहीं है।

नेताप्रतिपक्ष डा चरण दास महंत, गरीब की दुख सुनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अध्यक्ष दयालु है, दिल दरिया है, उसमें किसान या आदिवासी समा सकता है, चर्चा होनी चाहिए।भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम के विपरीत चर्चा की मांग हो रही। पूर्व

सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सत्र आहूत होने के बीच आत्महत्या हुई है, बाद में चर्चा संभव नहीं है, इसे ग्राह्य करके चर्चा कराया जाए। धरमलाल कौशिक ने कहा, अगले सत्र में नियम के तहत चर्चा हो सकती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, नियम में यही है कि एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा सत्र के मध्य जो घटना होती है उस पर चर्चा होती है इसे ग्राह्य किया जाए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, यह विषय आधारित सत्र है। कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा, किसान आत्महत्या न करे इसलिए चर्चा आवश्यक है।

अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले किसान की मौत पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। इसके बाद हंगामे के बीच विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। इसी बीच सदन में नारायणपुर में किसान आत्महत्या पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया। अजय चंद्राकर ने कहा, स्थगन की सूचना नहीं है, इससे पहले व्यवस्था आनी चाहिए।

आसंदी की व्यवस्था के अनुसार पूर्व में ही स्थगन और चर्चा के मांग की सूचना दी जाती है। अल्प सूचना में स्थगन ध्यानाकर्षण नहीं लिया जा सकता है। आसंदी ने स्थगन सूचना को अग्राह्य कर दिया। चर्चा नहीं कराने के विरोध में विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया।

अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने धान खरीदी और किसानों की कर्जमाफी के मुददे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा, 21 क्विंटल धान खरीदी पर सरकार स्पष्ट नहीं है। सहकारी समितियों में लिमिट तय कर दी गई है। उन्होंने कहा, दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी को लेकर भाजपा नेताओं का बयान और वीडियो है, लेकिन अब सरकार कर्जमाफी पर मुकर रही है। 3100 रुपये में एकमुश्त खरीदी की मोदी गारंटी फेल हो चुकी है। अभी तक 3100 रुपये में एकमुश्त खरीदी का आदेश जारी नहीं हो पाया है।

उमेश पटेल ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, महतारी वंदन योजना का फार्म के कारण इनको बढ़त मिली है। इस योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया है।यानि सिर्फ 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। 70 लाख महिलाओं को यह धोखा देना चाहते हैं। किसानों को ठगा अब महिलाओं को ठगने जा रहे हैं.बिजली बिल हाफ योजना पर उमेश पटेल ने सदन में सरकार से पूछा, क्या इस योजना को बंद कर रहे हैं क्या? सरकार इस पर जवाब दें।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, यह अनुपूरक बजट मोदी की गारंटी का बजट है। पिछली सरकार एटीएम का बजट था कि कैसे छत्तीसगढ़ का पैसा बाहर भेजा जाएगा। भाजपा का अनुपूरक बजट 12 हजार करोड़ से ज्यादा का है। चंद्राकर ने कहा, महतारी वंदन योजना के तहत हम हर विवाहित महिला को 1000 रुपये देंगे। हम अपने वादे पर कायम है। यह मोदी की गारंटी है। हवा हवाई नहीं है। पीएम आवास में एक मकान आपने स्वीकृत नहीं किया। गरीबों का श्राप आपको लगा है, इसलिये आप विपक्ष में बैठे हैं। हमारी हर घोषणाएं मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराया। उन्होंने कहा, शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई जायज थी। एक साल में 2100 करोड़ रुपये का घोटाला और पांच साल में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है।

बिरनपुर की घटना पर कांग्रेस के तत्कालीन विधायक की भूमिका रही कि नहीं इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में सनातन धर्म का अपमान हुआ। चंद्राकर ने कहा, कांग्रेस के फ्लैगशिप योजना नरवा-गरवा-घुरूवा-बाड़ी में हुए घोटाले की आयोग बनाकर जांच होनी चाहिए। पीएससी, स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर घोटाला किया गया। राम के नाम पर पैसा खाने का काम कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। प्रदेश में कई स्थानों पर मूर्ति के नाम पर घोटाला हुआ। गोबर घोटाले की जांच की जानी चाहिए। इतना ही नहीं पैरा दान के नाम पर भी कई घोटाले हुये हैं।

अजय चंद्राकर ने झीरम कांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई, उमेश पटेल ने किया समर्थन

रायपुर। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने झीरम मामले पर सीबीआई जांच की उठी मांग को लेकर कहा, हमने झीरम घटना पर एसआईटी गठन किया। एनआईएन ने इसे चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच से मना किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच के लिए अनुमति दी। तब तक सरकार बदल गई। अजय चंद्राकर ने सीबीआई जांच की मांग की, मैं स्वागत करता हूं। हम इसके पक्ष में है। बिरनपुर घटना की भी सीबीआई जांच कर सकते हैं, उनकी सरकार है।

पटेल ने भाजपा सरकार की नियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, महतारी वंदन योजना उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार बनाने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार बनते ही सभी विवाहित महिलाओं को देने का वादा किया था, उनका धोखा सामने आ गया है। उमेश पटेल ने कहा, बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान रखा है। एक करोड़ विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में है और यह सिर्फ 30 लाख को इसका लाभ देंगे। 70 लाख महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। यह सरकार भगवा नहीं ठगवा सरकार है। ठगवा सरकार अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुकी है।

संक्षिप्त समाचार

किरण सिंह देव बने भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष, जगदलपुर से हैं विधायक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किरण सिंह देव को भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किरण सिंह देव को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। किरण सिंह देव जगदलपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। किरण सिंह देव रियासत कालीन जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वे महापौर भी रह चुके हैं। पेशे से अधिवक्ता किरण सिंह देव ने भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वे भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रहने के अलावा भाजाप के जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बिलासपुर संभाग के भाजपा के प्रभारी के तौर पर दायित्व संभाल रहे थे।

मुख्यमंत्री साय ने किया 'कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र' पुस्तक का विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुरुवार

को वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयंती के अवसर पर आचार्य मिश्र द्वारा पुनः संपादित एवं संयोजित 'कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र' नामक पुस्तक का विमोचन किया। गौरतलब है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता रहे पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1922-23 में जेल से हस्तलिखित कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र निकाला था। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र ने कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र को किताब के रूप में संकलित एवं संयोजित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आचार्य मिश्र को पंडित सुंदरलाल लाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र को सहेजकर पुनः संपादन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कृति के संकलन से युवा पीढ़ी को अपने पुराधाओं के संघर्ष और उनके योगदान को जानने-समझने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने जीरो पॉइंट चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज

राजधानी रायपुर में विधान सभा के समीप स्थित जीरो पॉइंट चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया।सौंदर्यीकरण के तहत चौक में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति एवं लोक कला को प्रदर्शित किया गया है।चौक के मध्य में और दोनों तरफ के गार्डन का सौंदर्यीकरण 37.95 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंँह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, विधायकगण, विधान सभा सचिव श्री दिनेश शर्मा भी उपस्थित हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, हलाल उत्पादों पर लगाना चाहिए प्रतिबंध, अगले सप्ताह तक करेंगे प्रयास

हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन के पदाधिकारी मिले मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री शर्मा से

■ मुख्यमंत्री साय बोले पूछताछ कर करेंगे कार्रवाई

रायपुर। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अन्न पदार्थ एवं उत्पादों को प्रमाणपत्र देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही है, निजी संस्थाओं को नहीं। लेकिन कुछ निजी मुसलमान संस्थाएं गैरकानूनी ढंग से हलाल प्रमाण पत्र देकर व्यापारियों को लूट रही हैं। इस गैरकानूनी हलाल प्रमाणपत्र एवं हलाल उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के पदाधिकारियों ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह विषय गंभीर है, ऐसा लगता है कि आज ही इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए; परंतु आने वाले सप्ताह में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करेंगे । मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर शिष्टमंडल में हिन्दू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ संगठक सुनील घनवट, बजरंग दल के अंकित द्विवेदी, मिशन सनातन के मदनमोहन उपाध्याय, श्री नीलकंठ महादेव संस्थान के पंडित नीलकंठ त्रिपाठी, किन्नर आखाडा की साध्वी सोम्या, छत्तीसगढ के हिन्दू जनजागृति समिति के मंगेश खंगन एवं हेमंत कानसकर शामिल थे। इस दौरान पर हलाल प्रमाणपत्र के गैरकानूनी होने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए, साथ ही उपमुख्यमंत्री को हलाल जिहाद विषय की भीषणता दिखाने वाली डॉक्यूमेंटरी दिखाई गई । इस अवसर पर दोनों मंत्रियों को मांग का निवेदन एवं हलाल जिहाद पुस्तक भेट दी गई ।

भाजपा राज्य में मंत्रीमंडल गठन गुटबाजी के चलते नहीं कर पा रही है: गुप्ता

रायपुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि भाजपा राज्य में मंत्री मंडल गठन गुटबाजी और अहंकार के चलते नहीं कर पा रही है जब से भाजपा राज्य में सत्ता प्राप्त की है तब से आज तक लोगों को भाजपा की गुटीय राजनीति सीधी तौर पर दिख रही है। पूर्व मंत्री रहे विधायकों का अहंकार स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।

सपा नेता नवीन गुप्ता ने आगे बताया कि राज्य में चुनाव हुए 12 जनवरी को दो माह पूर्ण हो जायेगा और 3 दिसम्बर को मतगणना के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को अस्तित्व में आए 23 दिन हो जायेगा। इतने लंबे अंतराल के बाद भी राज्य मंत्री परिषद का अस्तित्व में नहीं आना मंत्री मंडल का गठन नहीं होना पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है यह संदेहास्पद लग रहा है मंत्री पद की लालसा में कई लोग दिल्ली दरबार तक परिक्रमा कर आ गये हैं लेकिन मिला कुछ नहीं अब छत्तीसगढ़ की चुनी हुई सरकार में कौन मंत्री बनेगा उसका निर्णय अब दिल्ली से होगा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ फिर उनके विश्वासों के साथ कुठाराघात किया जायेगा।

मंत्री भी कौन बनेगा यह दिल्ली से थोपा जायेगा याने राज्य में क्या होना क्या नहीं होना है यह सब दिल्ली तय करेगी तो फिर यह कैसी लोकतंत्रीय व्यवस्थाा है चुनी हुई सरकार का निर्णय स्वयं न लेकर दिल्ली पर निर्भरता रहेगी।

भांचा राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजा जाएगा 300 मीट्रिक टन चावल

रायपुर। अयोध्या नगरी में श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य अब जल्द ही पूर्ण होने वाला है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों के अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में होने वाले इस महाआयोजन में भांचा राम के ननिहाल से 300 मैट्रिक टन चावल भेजा जाएगा। 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन चावल भेजेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हरी झंडी दिखाकर चावल से भरे ट्रकों को रवाना करेंगे।

छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया भगवान श्री राम लला मन्दिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। इस भव्य आयोजन में होने वाले भंडारे में प्रदेश के सभी राईस मिलर्स मिलकर अच्छी किस्म के चावल भेजेगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल होगे। 28 दिसंबर को वे ट्रकों को रवाना करेंगे।

बिलासपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय दुआ ने बताया अयोध्या में होने भगवान रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देश भर से श्रद्धालु बडी संख्या में पहुचेंगे। जिसके लिए आयोजन समिति की ओर से महा भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के बैनर तले सभी राइस मिलर्स मिलकर 300 मैट्रिक टन से अधिक चावल भेजेंगे। 15 से अधिक ट्रकों के माध्यम से चावल भेजा जाएगा।

दरअसल माता कौशल्या का मायका पुरातन कौसल प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ में ही था और चंद्रखुरी उनकी जन्म स्थल थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब अयोध्या में युवराज दशरथ का अभिषेक होने जा रहा था तब उस अवसर पर कौसल नरेश भानुमंत को भी आमंत्रित किया गया था। भानुमंत इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपनी पुत्री भानुमति के साथ आए। युवराज दशरथ को राजकुमारी भानुमति बहुत पसंद आईं। उन्होंने भानुमति से विवाह की इच्छा जाहिर की। तदुपरांत कौसल की राजकुमारी, दशरथ की रानी बन अयोध्या आ गईं। विवाह के बाद कौसल की राजदुहिता होने के कारण उन्हें कौशल्या नाम से पुकारा जाने लगा, जो आगे चलकर प्रभु श्री राम की माता बनीं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सभी जाति समुदाय के लोग बहन (कौशल्या) के पुत्र को भगवान के प्रतिरूप अर्थात भांजा मानकर उनका चरण पखारते हैं।

शहर जिला साहू समाज करेगा समाज के 12 विधायकों का सम्मान

युवक-युवती परिचय सम्मेलन 24 को, व्यापार एक्सपो का उद्घाटन 23 को

रायपुर। शहर जिला साहू संघ रायपुर आगामी दिनों छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान समाज की ओर से जीतकर आने वाले 12 विधायकों का सम्मान करने जा रही है। सम्मान समारोह का आयोजन कर्माधाम कृष्णा नगर में आयोजित किया गया है जहां पर 23 दिसंबर को व्यापार एक्सपो का उद्घाटन रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू करेंगे जबकि 24 जनवरी को युवक-युवती परिचय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल होंगे। दोनों ही दिन समाज की लाडली बेटी लोक गायिका आरु साहू अपना गायन प्रस्तुत करेंगी।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए अध्यक्ष केशवराम साहू, मेघराज साहू ने बताया कि विगम चार वर्षों से स्वजातीय व्यापारियों का व्यापार एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष 23 दिसंबर को कर्माधाम में होगा जिसका उद्घाटन रायपुर ग्रामीण के नवनिर्वाचित रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू करेंगे जबकि मुख्य अतिथि के रुप में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू तथा विधायक संदीप साहू, सामाजिक कार्यकर्ता छोटेलाल साहू, लोक गायिका आरु साहू अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर जिला साहू संघ के अध्यक्ष केशव राम साहू करेंगे। 24 दिसंबर को युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष अटल सिंह साहू करेंगे। इस अवसर पर साहू समाज की ओर से नवनिर्वाचित 12 विधायकों मोतीलाल साहू, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, संदीप साहू, इंद्र साव, ईश्वर साहू, इंद्रकुमार साहू, दीपे साहू, मोहित साहू, ओंकार साहू एवं बालेश्वर साहू का सम्मान किया जाएगा। युवती-युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अब तक 1500 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है।

मोदी की गारंटी के क्रियान्वयन में हमने एक सेकंड नहीं लगाया: मुख्यमंत्री

■ अनुपूरक बजट पर सीएम विष्णुदेव साय ने दिया जवाब

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुझे कुछ घंटे हुए थे, लेकिन मोदी जी की गारंटी का क्रियान्वयन करने हमने एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। सदन में प्रस्तुत अनुपूरक बजट, प्रदेश की जनता को मोदी जी द्वारा दी गई गारंटी पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार का पहला कदम है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व सरकार ने 1 लाख 21 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था, सरकार ने राजस्व की व्यवस्था नहीं की थी। 5 साल के कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी हम घोषणाएं पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं।

साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में राज्य के लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास देने की गारंटी है, इसलिए हमारी सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। 3 हजार 7 सौ 99 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण आवासों के लिए हमने इस अनुपूरक बजट में किया है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया ताकि छत्तीसगढ़ की जनता के सपनों को साकार किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए 2 साल के बकाया धान बोनस भुगतान के लिए द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए महतारी वंदन योजना का प्रावधान हमने किया गया है। इसमें आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु द्वितीय अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10 वर्ष की उम्र में ही मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठ गया, मैं अपना जीवन छत्तीसगढ़ के नागरिकों की बेहतरी के लिए समर्पित करूंगा। अनुपूरक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हर घर तक नल से जल पहुंचाने की दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। 1 हजार 230 करोड़ रुपए का राज्यांश मद में प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1 हजार 102 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 255 करोड़ 25 लाख रुपए का राज्यांश प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार के घोषणापत्र में हर वर्ग के लिए हितकारी प्रावधान हैं।

मैंने जब कर्जमाफी की बात कही तब नहीं आया था भाजपा का घोषणापत्र : विजय शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किसानों की कर्जमाफी को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। चर्चा के दौरान विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाया। जिसपर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, 'मैनें जिस समय कर्जमाफी की बात कही थी, तब भाजपा का घोषणा पत्र नहीं आया था। बाद में बीजेपी का घोषणा पत्र आया और जनता ने उस पर जनादेश दिया'। विपक्ष के सदस्यों ने कर्जमाफी पर उठाए सवाल पर कहा कि, जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान के बाद सदन में तीखा विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि, 'मोदी की गारंटी में 21 क्विंटल 3100 में धान खरीदी की बात कही गई। जबकि हमने 20 क्विंटल की बात कही थी, तब इसका विरोध किया गया। बुधवार को 21 क्विंटल का आदेश जारी हुआ, लेकिन प्रावधान नहीं है। आदेश जारी कर दिया, लेकिन सोसायटी को आदेश दिया। 700 क्विंटल छोटी सोसायटी और 1600 से ज्यादा बड़ी सोसायटी नहीं खरीद पाएंगे। किसानों को न्याय योजना की चौथी क़िस्त दें। जल्द मंत्रिमंडल का गठन कीजिए, मुख्यमंत्री जी। बीजेपी ने कर्जमाफी की बात कही थी, लेकिन कर्जमाफी नहीं हुई। किसान कर्जमाफी नहीं होने से आत्महत्या कर रहे हैं।

मिमिक्री कांड से जाटों की नाराजगी भारी पड़ सकती है

संजय सक्सेना

राज्यसभा के सभापति और कद्दावर जाट नेता जगदीश धनखड़ का जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद ने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के भीतर मजाक उड़ाया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उसका हंस-हंस कर वीडियो बनाया उससे राजस्थान, हरियाणा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट काफी नाराज हैं। जाट समाज इसके खिलाफ महापंचायत बुलाकर बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। आम चुनाव से कुछ समय पूर्व विपक्ष का इस तरह का रवैया उसके स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। टीएमसी सांसद के मिमिक्री कांड से पश्चिम बंगाल में भले ही ममता बनर्जी की पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी के वीडियो बनाने वाले शर्मनाक कृत्य से राजस्थान और हरियाणा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा खेला हो सकता है, जिसका इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान उठाना पड़े तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं भाजपा मिमिक्री कांड से फायदे में नजर आ रही है। मिमिक्री कांड सामने आते ही बहुजन समाज पार्टी ने तो इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करते हुए इस घटना को दुर्घटना पूर्ण बता दिया है लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राष्ट्रीय दल के नेता चौधरी जयंत सिंह की चुप्पी से जाट समाज काफी आहत है। समय रहते इन दोनों नेताओं ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जाट बाहुल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, राज्यसभा सभापति पदेन उपराष्ट्रपति भी होता है। जगदीप धनखड़ पुराने जाट नेता हैं। उनकी उम्र भी हो चुकी है। नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जाट समाज का बोलबाला है। जाट समाज यूं तो किसी को वोट दे पर समाज के प्रतिष्ठित शख्सियत के अपमान पर एकजुट नजर आता है। वैसे भी एक बुजुर्ग आदमी की बॉडी लैंग्वेज का मजाक बनाना बेहद भद्दा है। उसमें भी अगर यह किसी सांसद द्वारा किया जाए यह तो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी की बात है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो किया वो गलत है, पर राहुल गांधी ने जो किया वो बहुत ही अभद्रता की श्रेणी में आ जाता है। राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं बनाते तो शायद यह मामला सामने आता नहीं आता क्योंकि आजकल तमाम दिग्गज हस्तियों की मिमिक्री के बहुत लोग वीडियो बना रहे थे और बहुत लोग देश के तमाम सम्मानित लोगों की बॉडी लैंग्वेज की नकल कर उनका मजाक बनाते रहते हैं। हो सकता है कि संसद में भी यह आए दिन होता हो। कल्याण बनर्जी को कौन जानता है। हो सकता है कि इसके पहले कल्याण बनर्जी पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भी इस तरह से हंसी उड़ा चुके हों पर चूंकि कल्याण बनर्जी को कोई जानता ही नहीं है इसलिए मामला तूल नहीं पकड़ता। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता हैं। इंडिया गठबंधन अगर अस्तित्व में आता है, चुनावों में विजयी होता है तो उन्हें पीएम बनते हुए भी हम देख सकते हैं। इसलिए उनका वीडियो बनाना लोगों और उसमें भी खास का जाट समुदाय को बिल्कुल भी नहीं पचेगा। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि इसको जाट समुदाय से जोड़कर देखना गलत है। उधर, दिल्ली और उसके आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय ने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है। जगदीप धनखड़ के समर्थन में पालम के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने कहा इस मुद्दे पर हमने प्रमुख लोगों की मीटिंग बुलाई है। फिलहाल अभी पंचायत नहीं बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि या तो टीएमसी सांसद माफी मांगें या हम बड़े स्तर पर पंचायत करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि उप राष्ट्रपति के हाव-भाव का प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाट समाज किसान परिवार का अपमान नहीं सहेगा।

दिग्गजों पर भारी कांग्रेस के जीतू पटवारी

सिद्धार्थ शंकर गौतम

मध्य प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा ने पीढ़ी परिवर्तन कर भविष्य का खाका प्रस्तुत किया है उसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस का पीढ़ी परिवर्तन भी भविष्य की राजनीति को दृष्टिगत रखकर ही हुआ है। तमाम बड़े दिग्गजों को किनारे कर अपेक्षाकृत युवा जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है कि अब वह भाजपा की लाइन पर चलकर उससे टक्कर लेगी।

युवाओं को आगे कर यह संदेश देने का प्रयास हुआ है कि अब कांग्रेस भी पुराने और चुके हुए नेताओं को ढोने के मूड में नहीं है। युवाओं को आगे बढ़ाने का कांग्रेस का निर्णय प्रदेश में कांग्रेस की पहचान बन चुके दिग्विजय और कमलनाथ के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि अब उनका युग समाप्ति होने को है और उन्हें युवाओं का नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा। तीनों के बहाने ही सही, दिग्विजय-कमलनाथ से असंतुष्ट नेताओं की भी पूछ-परख होगी और हाशिए पर पड़े नेताओं के दिन फिरेंगे।

मध्य प्रदेश की राजनीति में तीन दशक से अधिक समय तक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस के प्रदेश संगठन को अपने मुताबिक चलाया है। अपने परिवार और बड़ी संख्या में समर्थकों के चलते इन्हें केंद्रीय नेतृत्व से भी चुनौती कम ही मिली है। जो इनका समर्थक नहीं रहा, वह प्रदेश की राजनीति में टिक नहीं पाया। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की राजनीति तो कमलनाथ ने केंद्र की राजनीति की और दोनों ने आपसी सामंजस्य से प्रदेश संगठन को चलाया।

2018 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही दोनों के आपसी सामंजस्य में कमी आई। दोनों अपनी विरासत अपने पुत्रों को देकर सम्मानजनक विदाई चाहते थे और इसमें काफी हद तक सफल भी हो जाते किंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया की बग़ावत ने इनके सपनों पर कुठाराघात कर दिया। न सरकार बची, न साख। सिंधिया की विदाई दिग्विजय सिंह के खाते में जोड़ी गई। रही-सही कसर इस विधानसभा चुनाव में कुर्ताफाड़ राजनीति ने पूरी कर दी।

कांग्रेस के नेता भी समझने लगे कि इन दोनों के रहते उन्हें हमेशा दरबारी बनकर रहना पड़ेगा। अभी पिता के संरक्षण में हैं तो भविष्य बेटे की कृपादृष्टि पर चलना पड़ेगा। कांग्रेस आलाकमान भी यह समझ चुका था कि दोनों नेताओं के रहते प्रदेश में कांग्रेस का भला नहीं होने वाला किंतु उसे अवसर नहीं मिल रहा था कि इन्हें कैसे किनारे किया जाए। चुनावी हार ने नेतृत्व की यह इच्छा तो कम से कम पूरी कर दी है। दिग्विजय सिंह के आधा दर्जन रिश्तेदार और तीन दर्जन से अधिक समर्थक चुनाव हारे, वहीं कमलनाथ के समर्थक भी बड़ी संख्या में हारे हैं।

कमलनाथ छिंदवाडा बचाने का श्रेय ले सकते हैं किंतु उनके लिए भी अब वहां कुछ बचा नहीं है। बेटे नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य की चिंता उन्हें करनी है। हालांकि प्रदेश में वर्तमान नियुक्तियां यह संकेत कर रही हैं कि प्रदेश से दिग्विजय-कमलनाथ युग की समाप्ति की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार, कमलनाथ अपने खास समर्थक बाला बच्चन के लिए प्रदेश अध्यक्ष और स्वयं के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद चाहते थे। वहीं दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे। किंतु कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ के धुर विरोधी जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह के धुर विरोधी उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाकर यह संदेश दे दिया है कि अब वह प्रदेश में इन दोनों की छाया से मुक्त होना चाहता है।

कमलनाथ से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी सामने भी आने लगी है क्योंकि संगठन में बदलाव के तुरंत बाद ही उनके मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले की नेमप्लेट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तोड़कर फेंक दी गई है। वहीं कमलनाथ से केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी तो और बढ़ गई है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव का 100 करोड़ के खर्च का ब्यौरा कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय को भेज दिया है। हालांकि चुनाव पूर्व सारा खर्च वहन करने का दंभ कमलनाथ ने भरा था।

राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। अनुसूचित जाति के खाती समाज से आने वाले जीतू पटवारी ने सड़क से सदन तक संघर्ष कर अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता की है। भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के लगभग सभी जमीनी संघर्षों में पटवारी ने ही युवाओं का नेतृत्व किया है। हालांकि उनका बड़बोलापन उन पर भारी पड़ता रहा है किंतु राहुल गांधी से उनकी करीबी और सर्वमान्य युवा नेता की छवि ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद दिलाया है। अनुसूचित जाति वर्ग एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था किंतु नरेंद्र मोदी की सोशल इंजीनियरिंग के चलते भाजपा को इस वर्ग का साथ मिला है जिसे कांग्रेस वापस पाना चाहती है।

जीतू पटवारी मालवा से आते हैं और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी इसी क्षेत्र से हैं तो अब प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु मालवा बन गया है। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र दोनों राजनीतिक दलों के लिए महत्त्वपूर्ण है अत: पटवारी को नेतृत्व देकर कांग्रेस इस क्षेत्र में अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है।

वहीं अपनी बुआ पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व. जमुना देवी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले उमंग सिंगार की छवि जुझारू नेता की है और कांग्रेस में उन्हें बड़ा वनवासी नेता माना जाता है। 2001 में मप्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से होते हुए उमंग सिंगार चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। निमाड़ क्षेत्र से आने वाले उमंग सिंगार न सिर्फ अपनी गंधवानी सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट में तब्दील कर चुके हैं वरन आसपास की कई सीटों पर उनके प्रभाव का सिक्का चलता है। वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति में वनवासी वर्ग सबसे अहम माना जाता है और राज्य की 47 विधानसभा सीटें वनवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं जबकि लगभग 100 सीटों पर इस वर्ग का सीधा प्रभाव रहता है।

ऐसे में कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। उमंग सिंगार जिस धार जिले से आते हैं वह भोजशाला के चलते हिंदुत्व की राजनीति का गढ़ होने के साथ ही एकमात्र जिला है जिसने प्रदेश को चौथा नेता प्रतिपक्ष दिया है। उमंग सिंगार के सामने जिले के साथ ही क्षेत्र की हिंदूवादी राजनीति के बीच कांग्रेस को मजबूती देने का दबाव होगा।इसके अलावा ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के ब्राह्मण चेहरे हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने ब्राह्मणों को साधने का प्रयास किया है। यह क्षेत्र जाति की जकड़न में कैद है और यहां ब्राह्मण वर्ग राजनीतिक रूप से मुख्य भूमिका में है। फिर उत्तर प्रदेश से सटे होने के चलते वहां के ब्राह्मणों को भी हाथ के साथ का संकेत देने का प्रयास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को ब्राह्मण विरोधी बनाने का प्रयास लंबे समय से चल रहा है।

हालांकि एक समय रेप के मामले में फरार रहे पूर्व गृहमंत्री स्व. सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे को अपनी छवि सुधारने के साथ क्षेत्र के ही बड़े ब्राह्मण नेताओं से चुनौती मिलेगी और यदि वे इस चुनौती से पार पाने में सफल होते हैं तो सिंधिया लॉबी को पछाड़ सकते हैं और कांग्रेस का नया ब्राह्मण चेहरा बन सकते हैं। तीनों नेताओं के समक्ष चुनौतियां भले ही बड़ी हों किंतु यदि तीनों ने इनसे पार पाकर कांग्रेस की बंजर हो चुकी जमीन को हरा-भरा कर दिया तो आने वाला समय इन्हीं नेताओं का रहने वाला है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामण्युपनिषद् (भाग-18)

गतांक से आगे...

पुन: हृदयकमल में स्थित प्रज्वलित ज्वालासदृश भगवान् सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी के लिए सुखदायी होता है। प्राणायाम में सर्वप्रथम इडा नाड़ी अर्थात् बायें स्वर से श्वास खींचे (पूरक करे)। पुन: पिंगला नाड़ी अर्थात् दायें स्वर से श्वास का रेचन करे (पुन: इसके विपरीत करे)। इस प्रकार प्राणायाम करते समय चन्द्र और सूर्य दोनों का पूर्व वर्णित तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र दो महीने में नाड़ीशोधन हो जाता है।

नाड़ीशोधन प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती। है तथा आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्यनाद सुनाई पड़ने लगता है। प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे, तब तक अपान वायु को भी रोके रखे। इस प्रकार हृदयाकाश में एक श्वास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है। प्राणायाम की पूरक, कुम्भक और रेचक ये तीनों क्रियाएँ साक्षात् प्रणव का ही रूप हैं (इस चिन्तन के साथ) द्वादश मात्रायुक्त प्राणायाम करना चाहिए।

सूर्य और चन्द्र का यह द्वादश मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है। पूरक में द्वादश मात्रा, कुम्भक में षोडश मात्रा और रेचक में दस मात्रा के प्राणायाम को ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम द्वादश मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी तिगुनी अर्थात् छत्तीस मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है। अधम अर्थात् सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है, मध्यम प्राणायाम में शरीर काँपने लगता है तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है, इसलिए इसी तरह का प्राणायाम करना चाहिए।

क्रमश: ...

'राष्ट्रीय गणित दिवस'

योगेश कुमार गोयल

प्रतिवर्ष 22 दिसम्बर को भारत में 'राष्ट्रीय गणित दिवस' मनाया जाता है, जो देश के महान् गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन को सम्मान देने के उद्देश्य से उनकी स्मृति में उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है।

करीब एक दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने चेन्नई में रामानुजन की 125वीं जयंती समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि ऐसे प्रतिभावान तथा गूढ़ ज्ञान वाले पुरूषों और महिलाओं का जन्म कभी-कभार ही होता है। गणित में रामानुजन के अविस्मरणीय योगदान को याद रखने और सम्मान देने के लिए उसी अवसर पर रामानुजन के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 22 दिसम्बर को 'राष्ट्रीय गणित दिवस' मनाए जाने का निर्णय लिया गया था।

मद्रास से करीब चार सौ किलोमीटर दूर तमिलनाडु के ईरोड शहर में 22 दिसम्बर 1887 को जन्मे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का बचपन कठिनाइयों और निर्धनता के दौर में बीता था। तीन वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे और तब परिवार के लोगों को चिंता होने लगी थी कि कहीं वह गूंगे न हों लेकिन कौन जानता था कि यही बालक गणित के क्षेत्र में इतना महान् कार्य करेगा कि सदियों तक दुनिया उन्हें आदर-सम्मान के साथ याद रखेगी। उन्हें गणित में इतनी दिलचस्पी थी कि गणित में उन्हें प्राय: सौ फीसदी अंक मिलते थे लेकिन बाकी विषयों में बामुश्किल ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते थे क्योंकि गणित के अलावा उनका मन दूसरे विषयों में नहीं लगता था। उन्होंने कभी गणित में किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया था।

गणित में अतुलनीय योगदान के लिए श्रीनिवास रामानुजन को के. रंगनाथ राव पुरस्कार भी दिया गया था। उनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे विषयों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी वे गणित के ही प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित के अलावा दूसरे सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए और इस कारण उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद हो गई। परिवार की आर्थिक हालत पहले ही ठीक नहीं थी, इसलिए परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने गणितज्ञ रामास्वामी अय्यर के सहयोग से मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी करनी शुरू की। नौकरी के दौरान भी वे समय मिलते ही खाली पन्नों पर गणित के प्रश्नों को हल करने लग जाया करते थे।

एक दिन एक ब्रिटिश की नजर उनके द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्नों पर पड़ी तो वह उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। उसी अंग्रेज के माध्यम से रामानुजन का सम्पर्क जाने-माने ब्रिटिश गणितज्ञ और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एच हार्डी से हुआ। हार्डी ने उनकी विलक्षण प्रतिभा को भांपकर उन्हें अपनी प्रतिभा को साकार करने के लिए लंदन बुला लिया और उनके लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में व्यवस्था की, जिसके बाद उनकी ख्याति दुनियाभर में फैल गई।

नेपाल में क्यों उठी राजतंत्र बहाली की मांग

चंद्रभूषण

'नेपाल में राजतंत्र के समापन की घोषणा तब हुई थी, जब भारत में सोनिया गांधी के प्रभाव वाली सरकार मौजूद थी। अभी जब हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा ने वहां इतना जोर पकड़ लिया है तो नेपाल पर इसका कुछ तो व्यवस्थागत प्रभाव पड़ेगा ही।' लेकिन उनकी अपनी राय है कि यह सोच नेपाल में आए बदलाव के आंतरिक कारणों की अनदेखी पर आधारित है। 'लोकतंत्र में समस्याएं झेल रहे लोगों ने राजतंत्र में इससे कहीं ज्यादा चौतरफा बदहाली देख रखी है।'

नेपाल में राजतंत्र और 'हिंदू राष्ट्र' को फिर से बहाल करने को लेकर प्रदर्शनों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। 15 दिसंबर से राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) ने इन्हीं दोनों मुद्दों पर दो महीने का 'जनजागरण अभियान' चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के बाद उसकी योजना 'मेची से महाकाली तक' यानी नेपाल के पूरबी और पश्चिमी छोरों को जोड़ती हुई एक जागरण यात्रा निकालने की है। आरपीपीके पास नेपाली संसद में 14 सीटें हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों का नेतृत्व उसके हाथ में नहीं था। यूं कहें कि इनके बारे में उसका नजरिया दुविधाग्रस्त था।

नवंबर में हुए प्रदर्शनों में केंद्रीय भूमिका नेपाल के सुदूर पूर्वी जिले झापा के रहने वाले दुर्गा प्रसाई नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति की बताई जाती है, जिसके नजदीकी रिश्ते नेपाल की तीनों बड़ी पार्टियों से रहे हैं और जिसकी ख्याति 500 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर अदायगी के नाम पर सन्नाटा खींच जाने वाले व्यक्ति की है। यह कोई दबा-छिपा तथ्य नहीं है। इस आंदोलन का सबसे मुखर आर्थिक मुद्दा अब तक यही है कि सरकार के इशारे पर बैंक लोगों को खामखा कर्ज वसूली के लिए परेशान कर रहे हैं। राजतंत्र की वापसी हो गई तो रातोंरात यह जोर-जबर्दस्ती खत्म हो जाएगी और सारे कर्जे माफ कर देने के अलावा बैंकों के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा!

तीन साल पहले हुए ऐसे ही प्रदर्शनों के मुकाबले इस बार के प्रदर्शन यकीनन ज्यादा बड़े हैं। संसद में एक राजतंत्र समर्थक दल की मौजूदगी से इन्हें एक तार्किक स्वर मिला है। हालांकि राजा की प्रशंसक शक्तियों में आपसी अंतर्विरोध भी कम नहीं हैं। आरपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लिंग्डेन दुर्गा प्रसाई को 'अराजक शक्ति' बता रहे हैं और मीडिया से अपना नाम 'एक डिफॉल्टर के साथ तो न ही जोड़ने' का आग्रह कर रहे हैं। सवाल यह है कि दक्षिण एशिया के इस सबसे नए गणराज्य में लिखित संविधान लागू होने के मात्र आठ वर्षों के अंदर राजतंत्र की वापसी को लेकर शुरू हुई इस दूसरी सुगबुगाहट को किस तरह देखा जाए? गणराज्य, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद से नेपाल के लोगों का क्या सचमुच इतनी जल्दी मोहभंग हो गया है?

कुछ बातें निश्चय ही चिंताजनक हैं। मसलन यही कि सत्ता की ललक नेपाली राजनेताओं में बहुत ज्यादा है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहां पूरे-पूरे गुट के इधर से उधर होने की घटनाएं अक्सर देखी गई हैं। दूसरा मामला अस्तित्व के संकट का है। सत्ता के करीब नहीं रहे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, और अकेले पड़ गए तो जेल चले जाएंगे, इस तरह का एक डर सबको है। माओवादी धड़े में यह डर सशस्त्र संघर्ष के समय की गतिविधियों से जुड़ा है। बाकियों के साथ ऐसा मामला नहीं है तो उन्हें भ्रष्टाचार के किसी न किसी मामले में धर लिए जाने का डर है।

विचार को लेकर काफी सारा खूनखराबा वहां हो चुका है, लेकिन संसदीय राजनीति में वैचारिक पोलेपन का हाल यह है कि चीन के करीबी समझे जाने वाले कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली की पार्टी एनसीपी (यूएमएल) ने पिछला आम चुनाव राजतंत्र के पक्ष में खुलकर खड़ी पार्टी आरपीपी के साथ कई सीटों पर समझदारी बनाकर लड़ा।

इस गिरावट में कुछ भूमिका संयोगों की भी है। 2015 के विनाशकारी भूकंप ने नेपाल में आम लोगों के तो घर-बार तबाह किए ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। हालात कुछ सुधरने शुरू हुए तो कोरोना महामारी की रोक-छेक ने यहां की टूरिस्ट अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। कोरोना गया तो रूस-यूक्रेन युद्ध और अभी इस्राइल-फलस्तीन टकराव ने मुद्रास्फीति को बेकाबू कर दिया। इसके चलते ब्याज दरें डबल डिजिट में चल रही हैं और कर्ज अदायगी में चूक की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसका मतलब क्या यह लगाया जाए कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और भाषाई बहुलता के नाटक का पर्दा गिराकर 'एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा, एक राजा' वाले पुराने 'स्वर्णिम' दौर में वापस लौट जाने का वक्त आ गया है? तराई के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र किशोर जहां-तहां सुनने में आ रही इस बात का जिक्र करते हैं कि 'नेपाल में राजतंत्र के समापन की घोषणा तब हुई थी, जब भारत में सोनिया गांधी के प्रभाव वाली सरकार मौजूद थी। अभी जब हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा ने वहां इतना जोर पकड़ लिया है तो नेपाल पर इसका कुछ तो व्यवस्थागत प्रभाव पड़ेगा ही।' लेकिन उनकी अपनी राय है कि यह सोच नेपाल में आए बदलाव के आंतरिक कारणों की अनदेखी पर आधारित है। 'लोकतंत्र में समस्याएं झेल रहे लोगों ने राजतंत्र में इससे कहीं ज्यादा चौतरफा बदहाली देख रखी है।'

नेपाली लोकतंत्र में काफी कुछ मुझे ऐसा दिखता है, जो 1990 की शुरुआत तक मौजूद राजतंत्र के लिए कल्पना से भी परे था। मसलन, तामांग और नेवार जैसी बौद्ध जातियों को सरकारी तौर पर 'मतवाली' (पियक्कड़) जाति मानकर नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद संसद में इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। नेपाल की क्षेत्रीय पहचानें 'पहाड़ी' और 'मधेस' तक सीमित नहीं हैं, यह अनुभूति लोगों को फेडरलिज्म से होनी शुरू हुई है। नेपाली राजनेता अगर गिरने की होड़ ही न ठान लें तो लगता नहीं कि इन परिवर्तनों को पीछे छोड़कर लोग राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की ओर दौड़ लगाने लगेंगे।

आज का इतिहास

1961 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1964 लॉकहीड एसआर -71 ब्लैकबर्ड , संयुक्त राज्य एयरफोर्स की लंबी दूरी की, मच 3+ रणनीतिक टोही विमान और द वर्ल्ड की सबसे तेज हवा से चलने वाले मानवयुक्त विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी।
1972 ऑस्ट्रेलिया ने चीन और पूर्वी जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया।
1972 निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में आए 6.25 तीव्रता के भूकंप में 12 हजार से अधिक लोग मारे गए।
1974 ग्रांडे कोमोर, अंजून और मोहाली ने कोमोरोस के भरोसेमंद देश बनने के लिए मतदान किया।
1984 न्यूयॉर्क सिटी सबवे ट्रेन की सवारी करते समय, बर्नहार्ड गोएट्ज ने चार अफ्रीकी अमेरिकी युवकों को गोली मार दी, जिन्होंने उसे लूटने का प्रयास किया, सतर्कता, नस्लवाद और आत्मरक्षा की कानूनी सीमाओं पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई।
1988 स्कॉटलैंड की सीमा के नजदीक लॉकरबी शहर में एक पैन एम का जंबो जेट 258 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
1989 डेनवर में माइनस 18 डिग्री एफ, -23 डिग्री एफ में कांसस सिटी, मिसौरी, -42 डिग्री एफ में स्कॉट्सब्लफ नेब्रास्का -47 डिग्री एफ, हार्डिन मॉन्ट में स्न और ब्लैक हिल्स साउथ डकोटा में -60 डिग्री एफ।
1997 हुसैन फ़राह ऐदिद ने सोमालिया के पूर्वजन्म के विवादित शीर्षक को त्याग दिया।
2001 उत्तरी गठबंधन के बुरहानुद्दीन रब्बानी ने हामिद करजई के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को पॉवरिन अफगानिस्तान सौंप दिया।
2010 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिकता से जुड़े कानून पर दस्तखत कर सेना में समलैंगिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया।
2010 संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेना में समलैंगिकों पर अपनी विवादास्पद डोन्ट आस्क, डॉन्टेल नीति को दोहराया।
2011 देश के जाने-माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट पी.के. अयंगर का निधन हुआ।
2011 दक्षिणी चीन के हैमेन में एक बिजली संयंत्र के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को आंसुओं के साथ निकाल दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

भतीजे को बसपा की कमान सौंपना युवा चेहरा देने की कोशिश

अजय बोस

लोकसभा चुनाव अब चंद माह दूर हैं। लेकिन उससे ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने 28 वर्षीय भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का फैसला उनकी थकी हुई और राजनीतिक परिदृश्य से तेजी से ओझल होती पार्टी को युवा रूप देने की एक हताश कोशिश लगती है। उनके इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह है कि पार्टी से युवा दलित समर्थकों का पलायन रोका जाए, जिनमें उनकी अपनी जाटव उपजाति के लोग भी शामिल हैं, जो चुनावों में दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद अभी हाल तक पार्टी के वफादार बने हुए थे। लंदन से शिक्षाप्राप्त व एमबीए डिग्रीधारक युवा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर मायावती एक ऐसे राजनीतिक दल को आधुनिक चेहरा देने की उम्मीद कर रही हैं, जो वक्त के साथ तेजी से पिछड़ता जा रहा है।

हालांकि इसका कतई यह मतलब नहीं कि बहन जी का सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा है। उन्होंने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड उनके ही क्षेत्र रहेंगे, जबकि उनका भतीजा देश के दूसरे स्थानों पर पार्टी के हितों की देखभाल करेगा। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि मायावती पार्टी के भीतर पहले की तरह ताकतवर बनी रहेंगी और युवा बसपा नेता उनके इशारों पर ही चलेंगे।

अपने गुरु कांशीराम की तरह अपने उथल-पुथल भरे राजनीतिक कॅरिअर के ज्यादातर समय के दौरान वंशवादी राजनीति से दूरी बनाए रखने वाली बहन जी ने पहली बार अपनी पुरानी सोच से हटने के संकेत करीब पांच साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दिए, जब उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को बसपा का उपाध्यक्ष और उनके बेटे आकाश को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया। हालांकि पूरे परिवार में आनंद उनका चहेता माना जाता रहा है, लेकिन जब वह सत्ता में थी, तब भी उन्होंने आनंद को पार्टी या सरकार के भीतर कोई पद लेने से हतोत्साहित ही किया। अब अगर मायावती अपने भतीजे आकाश को बसपा के भविष्य के रूप में देख रही हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई वर्षों से बसपा में कांशीराम द्वारा शुरू किए गए सामाजिक- राजनीतिक आंदोलन की झलक मिलनी बंद हो चुकी है और अब वह भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह एक नेता- केंद्रित पार्टी बन गई है।

अपने उत्कर्ष के दिनों में जब बहन जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अपनी महानता के चरम पर थीं, तब उन्होंने जमीनी पार्टी समन्वयकों और प्रमुख नौकरशाहों व राजनीतिक सलाहकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब वह राजनीतिक मोर्चे पर तेज व अपरिवर्तनीय गिरावट का सामना कर रही हैं, यह मॉडल उनके किसी काम का नहीं साबित हो पा रहा है और भारतीय राजनीति के बदलते माहौल में अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने परिवार की तरफ रुख करने के अलावा शायद उनके पास दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है।

दुर्भाग्यवश बसपा सुप्रीमो और उनके युवा राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए उस पार्टी को संभालने का यह आसान समय नहीं है, जिसने भारतीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात करने का वादा किया था। देश भर में बार-बार चुनावी पराजय बसपा के लिए सामान्य बात हो गई है। पिछले साल पार्टी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में करारा झटका लगा था, जब वह राज्य विधानसभा चुनाव में 403 सदस्यीय विधानसभा में महज एक सीट पर सिमट गई थी, जो अब तक उसका सबसे खराब प्रदर्शन भी था। देश के दूसरे हिस्सों में भी बसपा की हालत खराब ही होती जा रही है। चार राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों का हालिया दौर बसपा के कमजोर से भी कमजोर स्थिति तक पहुंचने की दुखद कहानी बताता है, बावजूद इसके कि इन चारों राज्यों में मायावती, उनके भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश ने प्रचार अभियान में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी।

राजस्थान में जहां मायावती ने आठ रैलियां कीं, वहां बसपा की सीटों की संख्या पिछले चुनाव के छह से घटकर इस बार सिर्फ दो रह गईं और उनका वोट प्रतिशत भी चार फीसदी से गिरकर सिर्फ 1.8 फीसदी रह गया। मध्य प्रदेश में बहन जी ने नौ चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, पर उनकी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। हालांकि पिछले चुनावों में बसपा को दो सीटे मिली थीं। छत्तीसगढ़ में भी उसकी झोली खाली रही और वोट शेयर भी आधा हो गया। बसपा के लिए तेलंगाना की स्थिति भी बुरी रही, जहां मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी के लिए एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के होने के बावजूद बसपा बमुश्किल एक फीसदी वोट पा सकी। विदेशी शिक्षा प्राप्त अपने युवा भतीजे को आगे बढ़ाकर बसपा को पुनर्जीवित करने की उनकी कोशिशों में दम नहीं दिखता, क्योंकि पार्टी में अब पहले जैसा वैचारिक साहस और संगठनात्मक गतिशीलता नहीं दिखती, जिसके दम पर एक-डेढ़ दशक पहले बसपा ने खासकर उत्तर प्रदेश और सामान्य तौर पर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। अब कुछ ही दलित होंगे, जो बहन जी को ऐसा नेता मानते हों, जो सदियों से चले आ रहे उनके उत्पीड़न को रोककर उनकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं।

एक वक्त था, जब बसपा सुप्रीमो को खासकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का पूरा समर्थन मिला हुआ था, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादातर लोगों को विश्वास हो चला है कि वह सत्तासीन मोदी सरकार के इशारों पर काम करती हैं, जो उनकी पार्टी का इस्तेमाल अल्पसंख्यक और दलित वोटों को बांटने के लिए कर रही थी, जिससे चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचे। मायावती ने हाल ही में दो बेहद लोकप्रिय युवा मुस्लिम नेता इमरान मसूद और दानिश अली को खो दिया, जिनमें से एक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित और दूसरे को निलंबित कर दिया गया। मसूद पहले ही अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अली के भी उनके ही नक्शेकदम पर चलने की संभावना है। अपने मूल दलित आधार को तेजी से खोती और पार्टी से खफा मुस्लिमों की बढती संख्या को देखते हुए बसपा को अपने वर्तमान गतिरोध से बाहर निकलने के लिए किसी राजनीतिक चमत्कार की जरूरत है। बहन जी के लिए यह एक शानदार कॅरियर का अपमानजनक अंत दिख रहा है। उनके भतीजे के उड़ान भरने से पहले ही उसके गिरने की आशंका बिल्कुल स्पष्ट है।

जदयू की 17 सीटों पर भाजपा को जिताऊ चेहरों की तलाश

लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सभी दलों ने तेज कर दी है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है और अब विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू होगा। वहीं बिहार में इसबार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। जदयू इसबार भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर दमखम वाले उम्मीदवारों की तलाश में है। ये 17 सीटें वे हैं जहां पिछली दफा 2019 में 16 पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। झंझारपुर, वाल्मीकीनगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, किशनगंज, जहानाबाद और गया लोकसभा सीट पर पिछली दफा एनडीए में जदयू के उम्मीदवार रहे थे। किशनगंज की सीट कांग्रेस के खाते में गयी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के भीतर दो बड़े दल जदयू और भाजपा के बीच 17-17 सीटों का बंटवारा हुआ था। यानी जदयू को 17 और भाजपा के उम्मीदवार 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। बाकी की छह सीटें लोजपा को दी गयी थीं। इस बार जदयू एनडीए से बाहर होकर इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। इसके कारण जदयू कोटे की सभी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर,सासाराम और पटना साहिब की सीट पर जदयू और कांग्रेस आमने-सामने रही थी। इस बार दोनों ही दल एक ही गठबंधन में शामिल हैं। पिछली बार यानी लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को राज्य की 40 में 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जीती हुई 17 सीटों के मौजूदा सांसदों के इतर जदयू कोटे की सीटों पर कई उम्मीदवार टिकट के दावेदार हैं। सीतामढ़ी की सीट पर जदयू ने पिछली बार भाजपा से आये सुनील कुमार पिंटू को उम्मीदवार बनाया था। पिंटू ने जाति गणना में अपनी जाति को लेकर सवाल उठाया है। जदयू इसे अनुशासनहीनता मान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है। दूसरी ओर भाजपा हर हाल में इस सीट पर अपनी जीत चाह रही है। इसी प्रकार झंझारपुर, वाल्मीकीनगर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा और गया की सीट पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं। भाजपा इस बार इन सभी सीटों पर उम्मीदवार की तलाश में है। ऐसी संभावना है कि गया की सीट पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को मिल सकती है। वहीं जमुई, नवादा,खगड़िया, हाजीपुर और वैशाली में लोजपा पिछली बार चुनाव लड़ी थी। इस बार भी लोजपा को छह सीटें मिल सकती हैं। हम के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद की पसंद काराकाट समेत और भी सीटें हो सकती हैं। मिथिलांचल की झंझारपुर की सीट पर 2014 में भाजपा के वीरेंद्र कुमार चौधरी यहां से सांसद रहे थे। 2019 के चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में चली गयी। इस बार भाजपा के कई नेता इस सीट के दावेदार हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा भी झंझारपुर में हो चुकी है। वाल्मीकीनगर लोकसभा सीट की भी यही कहानी है। 2014 में भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर देशभर में सियासी माहौल बन चुका है। भाजपा इसबार बिहार में 40 सीटों को जीतने के उद्देश्य से तैयारी में जुटी है। इस बार नीतीश कुमार विरोधी खेमे के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर बात शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अपनी तैयारी तेज की है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वहीं हाल में ही भाजपा ने तीन हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनायी है। जिससे बीजेपी के हौसले बुलंद दिख रहे हैं।

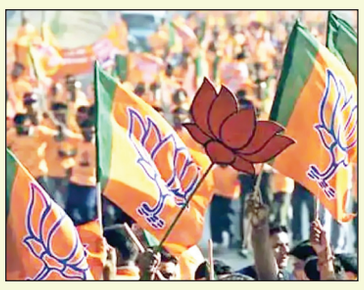

31 तक कैसे हो पाएगा इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा!

आशीष तिवारी

विपक्षी गठबंधन की बैठक में तय हुआ है कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर दस दिन में ऐसा क्या होगा कि गठबंधन के भीतर सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला तय होकर सभी सीटें घोषित हो जाएंगी। वहीं ढ्ढ.ह्ल.ष्ठ.ढ्ढ गठबंधन से जुड़ी पार्टी के नेताओं का कहना है कि गठबंधन की बैठक भले लंबे अरसे बाद हुई हो, लेकिन सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला पहले से तय हो चुका है। बस उसको लागू करके आगे की तैयारी शुरू करनी है। नई दिल्ली में सोमवार को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जटिल बिंदु सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला भी था। गठबंधन में शामिल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि लोगों को सीटों के शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबसे बड़ी रार नजर आती है। जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जो थोड़ी बहुत समस्याएं नजर आ रही थी, उनका तकरीबन निपटारा हो गया है। जबकि पंजाब में कुछ सीटों को लेकर आपसी समझ के साथ सीट शेयरिंग समझौता होना है। हालांकि सभी राज्यों में 31 दिसंबर या उसके आसपास तक सब कुछ फाइनल होकर आगे की रणनीति शुरू होगी।हालांकि सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों में गठबंधन के दल बगैर किसी आपसी समझौते के सियासी मैदान में उतर सकते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल और केरल को लेकर सबसे ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसलिए इन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी अलग चुनाव लड़ सकती है। जिसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में कांग्रेस के साथ दोनों की फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं बन रही हैं। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के सूत्रों का मानना है कि बाकी किसी भी राज्य में खासतौर से हिंदी भाषी राज्य में कोई समस्या नहीं है। इसे लेकर सोमवार की बैठक में खुलकर चर्चा भी हुई है। गठबंधन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक भले एक लंबे अरसे बाद हुई हो, लेकिन सीटों के बंटवारे से लेकर अन्य सभी जरूरी बातों पर लगातार मंथन होता रहा है। गठबंधन ने जिस तरीके से सभी दलों को एक साथ आकर केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के विरोध के लिए बड़ा मंच तैयार किया है, उस पर सहमति पहले भी बनी थी। लेकिन पांच राज्यों में हुए चुनावों के चलते उसे आगे लिए बढ़ा दिया गया था। अब 22 दिसंबर के बाद इसको सभी राज्यों में प्रमुखता के साथ शुरू किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक सदाकांत पुंडीर कहते हैं कि विपक्षी दलों के बीच में जिस तरह दस दिन का टाइम फ्रेम सीट शेयरिंग का दिया गया है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि तकरीबन सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। रही सही चर्चा है सोमवार को हुई बैठक में राज्य इकाइयों के माध्यम से पूरी करने की शुरुआत कर दी गई। इसके अलावा जिस तरीके से जनवरी तक गठबंधन के नेताओं ने सभी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में आने की योजना बनाई है, वह भी तकरीबन पहले से तय फॉर्मूले के आधार पर है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि गठबंधन में किसी भी तरीके की कोई समस्या न पहले थी न अब है।

खरगे का नाम पीएम के लिए करने चाल किसने चली

अमित शर्मा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खरगे को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का प्रस्ताव गठबंधन की बैठक के दौरान रखा था। कांग्रेस के धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल की ओर से ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को सहमति भी मिल गई थी। पहली नजर में इसे इंडिया गठबंधन की ओर से लाया गया मजबूत राजनीतिक दांव माना गया, क्योंकि इसके सहारे दलितों-पिछड़ों के वोट बैंक को साधकर पूरे देश में केंद्र सरकार के सामने मजबूत चुनौती दिए जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही थी।

लेकिन कुछ ही समय बाद इस प्रस्ताव के पीछे भी राजनीति की तलाश की जाने लगी। कहा जा रहा है कि खरगे को पीएम उम्मीदवार बताने का यह राजनीतिक दांव खुद कांग्रेस ने ही चला है। इसके सहारे उसने नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे उन नेताओं को ठिकाने लगा दिया, जो स्वयं को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनने के सपने देख रहे थे। चूंकि, मल्लिकार्जुन खरगे ने स्वयं ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया, संदेश यही गया कि विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी इसी पक्ष में है कि अभी प्रधानमंत्री पद पर कोई चर्चा न की जाए। चुनाव के बाद नेतृत्व के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपीए का गठन भी ठीक इसी तरीके से हुआ था। लेकिन यह प्रस्ताव पेश करके कांग्रेस ने नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे उन नेताओं की दावेदारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जो स्वयं को गठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाने के सपने देख रहे थे। जब गठबंधन का सबसे बड़ा दल खुद ही पीएम पद पर दावेदारी नहीं ठोंक रहा है, तो ऐसे में छोटे दलों के लिए यह अनैतिक हो गया कि वे सामने आकर अपने नेता के लिए पीएम पद के लिए दावेदारी करें। ध्यान देने की बात है कि इंडिया गठबंधन की

बैठक के दिन जदयू के एक विधायक ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया था। आज ही एक जदयू सांसद ने यह कहकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया कि नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को आकार दिया, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कब्जा कर लिया। इससे गठबंधन की दरारें भी सामने आ गई हैं। इसी तरह शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में यह कहकर कांग्रेस पर टिप्पणी की थी कि इंडिया गठबंधन में 27 घोड़े तो हैं, लेकिन इसका कोई सारथी नहीं है। यह दबाव नेता के रूप में किसी चेहरे पर सहमति बनाने के लिए थी। लेकिन माना यही जा रहा है कि इस खरगे को पीएम उम्मीदवार बनाने के दांव के सहारे कांग्रेस ने सभी पीएम पद के दावेवारों की जुबान बंद कर दी।

इंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा कि कुछ नेताओं के मन में स्वयं को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की लालसा हो सकती है, लेकिन कई दल ऐसे भी हैं जिनकी ओर से इस पद के लिए अभी कोई दावेदारी नहीं है। लालू प्रसाद यादव, उमर अब्दुल्ला, स्टालिन, वाम दल और कई अन्य पार्टियों-नेताओं की ओर से इस पद के लिए कोई दावेदार नहीं है। ऐसे में उन्हें किसी नाम के प्रस्ताव के साथ सामने आना चाहिए, जिससे एक नाम पर सहमति बने और गठबंधन को एक नेता दिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे भी राजनीति हो सकती है। कई दल साथ में अवश्य हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की बात आते ही उनकी आपसी खटास सतह पर आ सकती है। ऐसे में बेहतर यही है कि अभी इस पद पर किसी की दावेदारी सामने न आए और कांग्रेस ने यही आपसी संभावित खींचतान को समाप्त करने के लिए इस तरह की कोशिश की। जनता दल (यू) के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा कि पूरा देश यह जानता है कि जब विपक्ष का कोई दल साथ आने के लिए तैयार नहीं था, तब नीतीश कुमार ने इसके बारे में सोचा, और एक दूसरे के विरोध में खड़े दलों को भी एक गठबंधन के साथ आने के लिए तैयार किया। कार्यकर्ताओं-पार्टी नेताओं की भावना चाहे जो कुछ रही हो, उन्होंने स्वयं कभी प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी नहीं पेश की। हालांकि, वे यह मानते हैं कि समय रहते इंडिया गठबंधन को एक नेता, एक चेहरा मिलना चाहिए। इससे गठबंधन की लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है। अभी भी इंडिया गठबंधन के नाम से भाजपा परेशान है, यदि सही समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसी नेता को चुना जाए और सीट शेयरिंग की जाए, तो उनका मानना है कि 2024 में मोदी को रोकना मुश्किल नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कहा कि पूरा देश जानता है कि घमंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की आपस में कोई बात नहीं बनती। वे केवल मोदी का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह मल्लिकार्जुन खरगे का नाम सामने लाकर नीतीश कुमार का नाम काटा गया है, उससे भी यही साबित होता है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का काम किया गया है। इसके पहले कर्नाटक में भी यही बात हुई थी, और नीतीश कुमार को गठबंधन का नेतृत्व नहीं दिया गया था जिसके बाद वे नाराज होकर लौट आए थे। अब यह बात एक बार और सामने आ गई है और अब नीतीश कुमार को तय करना चाहिए कि वे कितना अपमानित होने के बाद भी इंडिया गठबंधन में बने रहते हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को काटने का काम स्वयं लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में कोई उनसे बड़ा नेता नहीं बने।

क्या देश और समाज का भला कर पाएगी दक्षिण को जोड़ने की सियासी कवायद

आर. राजगोपालन

तमिल संगमम दरअसल तमिल को हिंदी और तमिलवासियों को उत्तर भारतीयों से जोड़ने वाला एक प्रगतिशील कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा है। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्तर व दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना, देश की साझा विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि मंत्रालयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आईआईटी, मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि काशी और तमिलनाडु प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे में, इस कार्यक्रम का लक्ष्य साझा विरासत की समझ का निर्माण तथा इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को एक साथ लाना है। दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कारीगरी संबंधों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करना और इन्हें सशक्त बनाना भी इस उत्सव का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु और वाराणसी के विभिन्न सांस्कृतिक समूह काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।

काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हमारी ज्वलंत संस्कृति और भारतीयों के बीच गहरे तक जुड़े संबंधों का

जश्न मनाता है। यह %एक भारत, श्रेष्ठ भारत% की भावना को आगे बढ़ाता है, जिसकी पहचान आध्यात्मिक विश्वासों में भी निहित है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होंगे। इसके अतिरिक्त, 'नवाचार, व्यापार, ज्ञान विनिमय, शिक्षा तकनीक और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी' पर संगोष्ठी कराने की योजना बनाई गई है। लेकिन इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं।

भाजपा दरअसल, तमिलनाडु के द्रविड़ तर्क में राष्ट्रवाद को पिरोना चाहती है। अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मोदी वाराणसी में एक वार्षिक उत्सव के रूप में काशी तमिल संगमम को मनाने की बात बार-बार दोहराते रहे हैं। संगमम का उद्घाटन करते वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संगमम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है कि महादेव के एक घर से दूसरे घर में जाना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है, मदुरै मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसीलिए तमिलनाडु और काशीवासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वह अलग और अद्वितीय है।

पंद्रह दिनों के इस आयोजन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। महाकाव्यों का वाचन, सेमिनार और उत्तर प्रदेश के मंदिरों की झलक भी देखने को मिलेगी। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के बीच काव्यात्मक संबंध केदार घाट पर संत-कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा में भी परिलक्षित होते हैं।

तमिलनाडु के प्रतिनिधि वाराणसी की जीवंत सांस्कृतिक सहानुभूति का अनुभव कर रहे हैं और मनमोहक प्रस्तुतियां गंगा के किनारे स्थित पवित्र शहर की साझा संस्कृतियों की कालातीत कहानी बता रही हैं। इससे पहले थिरुक्कुरल को 16 अनुवादित संस्करणों (10 भारतीय भाषाओं, पांच विदेशी भाषाओं) और ब्रेल लिपि में जारी करने से जनमानस में भाजपा की सकारात्मक छवि बन रही है। इसके अलावा, उनकी खास पहल पर मणिमेखलाई सहित 46 तमिल व्याकरण ग्रंथों, संगम साहित्य और शास्त्रीय तमिल ग्रंथों के अनूदित संस्करण जारी करने से तमिल भाषियों में उनका सम्मान बढ़ा है।

जाहिर है कि एक खास उद्देश्य से शुरू किए गए इस संगमम को भाजपा पूरी गंभीरता से ले रही है। इससे काशी और तमिलवासियों के सांस्कृतिक एकीकरण का विचार द्रविड़ आंदोलन के मानस में गहराई से उतारने में कामयाबी मिली है। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण को साधने के उद्देश्य के साथ भाजपा ने काशी से कन्याकुमारी के बीच ट्रेन चलाई है। इसी ट्रेन से तमिलनाडु से आमंत्रित लोगों को बनारस लाया जा रहा है। मेहमानों की देखभाल का जिम्मा केंद्र सरकार के कई विभागों को दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इन्हें विशेष अतिथि का दर्जा दिया है। साथ ही सरकारी खर्च पर सभी को प्रयागराज और अयोध्या घुमाने की व्यवस्था भी की गई है। इन सभी प्रयासों की वजह सिर्फ यही है कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ा जाए। इसके अलावा, तथ्य यह भी है कि मोदी, योगी और अमित शाह की त्रिमूर्ति ने सधे कदमों के साथ दक्षिण भारत के संदर्भ में एक नई नीति पर चलने का फैसला किया। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा ने वर्ष 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल के बाद जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला लिया था।

भाजपा कुछ वैसा ही दक्षिण भारत में अपने वोटों में इजाफा करने के लिए करना चाह रही है। वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल की चाह रखने वाली भाजपा ने इस संगमम के जरिये उत्तर व दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक सेतु स्थापित किया है। भाजपा समझ गई है कि द्रविड़ अवधारणा तेजी से अपना प्रभाव खो रहे हैं। ऐसे में यही समय है, जब राष्ट्रवाद की अवधारणा को वहां जगह दी जाए।

काशी तमिल संगमम का एक राजनीतिक कारण तेलंगाना में कांग्रेस की जीत भी है। जाहिर है कि अब भाजपा के लिए दक्षिण की ओर देखो नीति को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। कुछ नेताओं ने ट्वीट किया कि कांग्रेस दक्षिण के लिए और भाजपा उत्तर के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी इसी विचार पर प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपने भाषण में भी किया, जिसकी बदौलत तमिल छात्रों को रिअल टाइम में तमिल में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने का रोमांचक अवसर मिला। इस तकनीक की बदौलत प्रधानमंत्री मोदी के सभी बाधाओं को ध्वस्त करते हुए बगैर मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्यों को पाने के विजन की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

कुंभ राशि वालों को शमी का पौधा लगाने से मिलेगी शनि दोष से मुक्ति

हिंदू धर्म में शमी के पौधे का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि शमी का पौधा भगवान शिव और शनिदेव को बेहद प्रिय है। इस पौधे को घर में लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। शनि दोष के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। वास्तु के अनुसार, घर में शमी का पौधा लगाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि गलत दिशा में शमी का पौधा लगाने से व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति पाने के लिए शमी का पौधा लगाते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए?

शमी के पौधे से जुड़े वास्तु के नियम

- वास्तु के अनुसार, शमी का पौधा घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं।
- मान्यता है कि शनिवार के दिन शमी के पौधे के नीचे दिया जलाने और पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है और जीवन के सभी दुख-कष्ट दूर होते हैं।
- वास्तु के नियम के मुताबिक, शमी के पौधे को भूलकर भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- शनिवार के दिन घर के मुख्यद्वार की बाई ओर शमी का पौधा लगाना मंगलकारी माना गया है। मान्यता है कि इससे नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलते हैं।
- वास्तु के अनुसार, शमी के पौधे के पास जूते-चप्पल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है।

शमी के पौधे का धार्मिक महत्व

मान्यता है कि शनिवार के दिन शमी के पौधे की नियमित पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति को शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या समेत शनि के अशुभ प्रभावों से मिलने वाले कष्टों से राहत मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सायंकाल में शमी के पौधे के पास दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है।

1 जनवरी को घर लाएं तांबे का सूर्य समेत ये शुभ चीजें, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

साल 2024 की शुरु होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। हर किसी की चाहत होती हैं कि आने वाला साल सुख-सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। हिंदू धर्म में धन-दौलत और खुशहाल जीवन के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना बेहद शुभ माना जाता है। साल 2024 के पहले दिन वास्तु की कुछ चीजों को घर ला सकते हैं। मान्यता है कि नए साल पर इन शुभ चीजों को घर लाने से परिवार के सदस्यों को सुख-सौभाग्य बढ़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन-संपदा में बरकत होती है। आइए जानते हैं कि नए साल पर किन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है?

तांबे का सूर्य

नए साल के मौके पर घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए तांबे का सूर्य ला सकते हैं। मान्यता है कि घर में तांबे का सूर्य लगाने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है और परिवार के सदस्यों को सभी कार्यों में सफलता मिलती है।

दक्षिणावर्ती शंख

नए साल के मौके पर घर में दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं। मान्यता है कि पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे जातक को कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है।

नारियल

साल 2024 के पहले दिन घर में नारियल जरूर लाएं और इसकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद नारियल को अपनी तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसों की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है।

गोमती चक्र

नए साल पर घर में गोमती चक्र भी ला सकते हैं। 11 गोमती चक्र को लाल या पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। धार्मिक मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा से धन का आवक बढ़ता है ।

मोर पंख

नए साल के पहले दिन घर में मोर पंख जरूर लाएं। कहा जाता है कि घर में मोर पंख लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।

धातु का कछुआ

वास्तु शास्त्र में, धातु के कछुए को सुख-समृद्धि का कारक माना गया है। कारोबार में बढ़ोत्तरी के लिए नए साल पर ऑफिस या घर में धातु का कछुआ स्थापित कर सकते हैं। इससे व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी और धन लाभ के योग बनेंगे।

घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखते समय इन बातों का रखें ध्यान, सुख-सौभाग्य में होगी वृद्धि

घर की साज-सजावट के लिए लोग अपने घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखते हैं। वास्तु के अनुसार, इस मूर्ति से घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ सुख-समृद्धि और खुशहाली भी आती है। घर की नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है और जीवन में आ रही सभी विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं, लेकिन घर में गलत तरीके और गलत स्थान पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने पर जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं घर की खुशहाली के लिए बुद्ध की प्रतिमा रखने के वास्तु के नियम...

घर में कैसे रखें बुद्ध की मूर्ति ?

मुख्यद्वार पर आशीर्वाद मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करना शुभ माना गया है।

भगवान बुद्ध की मूर्ति को भूलकर भी जमीन पर ना रखें। इसे हमेशा फर्श से 3-4 फीट ऊपर रखें। कहा जाता है इससे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियां आती हैं।

घर की पश्चिम दिशा में दाईं ओर झुके हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा को रखना बेहद लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।

वास्तु के अनुसार, घर के मंदिर में बुद्ध की मूर्ति को पूर्व दिशा में मुख करके रखें। इससे डर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है।

बच्चों के स्टडी रूम में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पूर्व की ओर मुख करके रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है।

वास्तु के अनुसार, डाइनिंग हॉल या लिविंग रूम में हाथ जोड़े हुए बुद्ध की मूर्ति रखना चाहिए। मान्यता है कि प्रार्थना करते हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने से वास्तु दोष दूर होता है।

बुधवार को गणेश जी के इस अचूक मंत्र का करें जाप, बिजनेस में होगी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की

वर्तमान समय में व्यापार को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर आप भी व्यापार करते हैं, तो बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक उचूक उपाय बताया गया है। जिसको पूरी श्रद्धा से अपनाए जाने पर यह हर स्थिति में फलदायी होता है।

आज के समय में पैसा हर इंसान की जरूरत बन चुका है। क्योंकि बिना धन के अर्थ प्रधान समय में कोई भी सुख संभव नहीं हैं। ऐसे में लोग पैसे कमाने के लिए तरह-तरह के जतन भी करते हैं। तो वहीं बहुत सारे लोग छोटे-मोटे व्यापार के जरिए आजीविका चला रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में व्यापार को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है।

प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापारियों की कमाई में कमी होती जा रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगर आप भी व्यापार करते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक उचूक उपाय बताया गया है। जिसको अपनाने से यह हर स्थिति में फलदायी होता है। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में...

बुद्धि के साथ व्यापार का कारक

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को नवग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। साथ ही बुध ग्रह को बुद्धि और व्यापार का भी कारक माना जाता है। बुधवार का दिन बुधदेव को समर्पित होता है। वहीं बुधवार को विधि-विधान से गणेश जी की

पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं। इसलिए व्यापारियों को बुधवार के दिन विधि-विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए।

रोजाना इस मंत्र का करें जाप

बुधवार को सुबह जल्दी स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा कर उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इसके साथ ही श्रीगणेश जी के मंत्र %ऊं गं ऊं% की एक माला रोजाना जाप करें। इस मंत्र का आप जितना अधिक जाप करेंगे, आपको उतना ही अधिक फल मिलेगा।

गणेशजी का यह पाठ सबसे उत्तम

बता दें कि अगर आप पर बुधदेव प्रसन्न नहीं हैं, तो आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल सकती है। बुधदेव की कृपा होने पर आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना फलेगा फूलेगा। बुधदेव की कृपा पाने के लिए जातकों को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। यह पाठ सबसे उत्तम फलदायी माना जाता है। वहीं व्यापार को बढ़ाने व फैलाने के लिए एक सिद्ध प्रयोग है। इस उपाय को कर आप भी अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं।

इतने दिन करें पाठ

आप बुधवार के दिन सुबह स्नान आदि कर गणेश जी की विधिविधान से पूजा करें। उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इस दौरान ध्यान रखें कि पूजा में तुलसी का इस्तेमाल न करें। फिर पूजा स्थल पर बैठकर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। नियमित रूप से 40 दिन तक इस पाठ का जाप करें। यदि आप पूरे श्रद्धाभाव से गणेश जी के इस अथर्वशीर्ष पाठ का जाप करते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही व्यापार भी बढ़ेगा। वहीं व्यापार करने वाले जातकों को इस पाठ का रोजाना जाप करना चाहिए।

रामायण की आरती करने से प्राप्त होती है श्रीराम की कृपा, पापों से मिलती है मुक्ति

रामायण की आरती से व्यक्ति को महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा जाता है और उसे भगवान श्रीराम की कृपा प्राप्त होती है। रामनवमी व अन्य मौके पर रामायण की आरती करनी चाहिए। हिंदू धर्म में रामायण को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान श्रीराम की लीला कथाओं का संकलन है। श्रीराम को सृष्टि के पालनहार श्रीहरि विष्णु का अवतार माना जाता है। वहीं रामायण की आरती श्रीराम की आरती है। मान्यता के अनुसार, रामायण की आरती से व्यक्ति को महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा जाता है और उसे भगवान श्रीराम की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में रामनवमी के मौके पर और अन्य दिनों में अपने कल्याण व श्रीराम की कृपा प्राप्ति के लिए रामायण की आरती करनी चाहिए।

रामायण की आरती

आरती श्री रामायणजी की। कीरति कलित ललित सिय पी की।।
गावत ब्रहमादिक मुनि नारद। बाल्मीकि बिग्यान बिसारद।।
शुक सनकादिक शेष अरु शारद। बरनि पवनसुत कीरति नीकी।।
आरती श्री रामायणजी की।।
गावत बेद पुरान अष्टदस। छओं शास्त्र सब ग्रंथन को रस।।
मुनि जन धन संतान को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की।।
आरती श्री रामायणजी की।।
गावत संतत शंभु भवानी। अरु घटसंभव मुनि बिग्यानी।।
ब्यास आदि कबिबर्ज बखानी। कागभुशुंडि गरुड़ के ही की।।
आरती श्री रामायण जी की।।
कलिमल हरनि बिषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की।।
दलनि रोग भव मूरि अमी की। तात मातु सब बिधि तुलसी की।।
आरती श्री रामायणजी की। कीरति कलित ललित सिय पीय की।।

भगवान राम स्तुति

नीलाम्बुज श्यामलकोमलांग सीता समारो पितवाम भागम।
पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघवशं नाथम।।

श्री जानकी वंदना

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम।
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नथोऽहं रामवल्लभाम।।

बिना पैसे खर्च किए दूर भगाएं घर की नेगेटिव एनर्जी, नहीं होगी धन की कमी

घर में पॉजिटिविटी रहती है माहौल खुशनुमा हो जाता है। वहीं, नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से परिवार और संबंधों में तनाव पैदा हो सकते हैं, जिससे घर की सुख-शांति छिन सकती है। घर में नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको ऐसे इजी तरीके बताने वाले हैं, जो घर की पॉजिटिविटी तो बढ़ाएंगे ही साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं।

वास्तु टिप्स-

1. घर को साफ-सुथरा रखें- घर में मौजूद गंदगी निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ-सुथरा रखने की कोशिश करें। वहीं, फालतू समान

इकट्ठा करके न रखें। कबाड़ को आज ही घर से बाहर करें।

2. दीपक जलाएं

घर के प्रवेशद्वार पर संध्या के समय रोज दीपक जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। मान्यता है संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है।

3. तोरण लगाएं

घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर भागने के लिए आम के पत्तों का तोरण बनाकर मुख द्वार पर लगाएं। ध्यान रखें की तोरण में इस्तेमाल किए गए पत्ते हरे-भरे होने चाहिए न की कटे-फटे।

4. नमक

अगर आपके घर में हर रोज क्लेश का माहौल बना रहता है तो हो सकता है इसके पीछे निगेटिव एनर्जी हो। इसलिए पानी में नामक मिलाकर पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है।

5. सूर्य को जल दें

रोजाना सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रह का संबंध मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा से माना जाता है।

6. तुलसी पूजन

तुलसी जी को रोजाना अर्घ्य दें और सुबह-शाम इनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी मां लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती हैं। वहीं, शुक्रवार का व्रत रखने और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करने से भी आर्थिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी से देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और एचडी रेवन्ना मिले

नईदिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव में

जनता दल (सेक्युलर) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कर्नाटक में सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत की अटकलों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान कुमारस्वामी के भतीजे और जद (एस) के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना सहित पार्टी के कुछ अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इस मुलाकात की तस्वीरें 'एक्स' पर साझा की और कहा, ''पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और एचडी रेवन्ना से मिलकर हमेशा खुशी होती है। देश की प्रगति में देवेगौड़ा के अनुकरणीय योगदान को भारत बहुत महत्व देता है। विविध नीतिगत मामलों पर उनके विचार व्यावहारिक और भविष्योन्मुखी होते हैं।''

इंडिया गठबंधन को बसपा प्रमुख मायावती ने दी नसीहत

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा)

अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) से दूरी बनाने वाले दलों के बारे में अनावश्यक टीका—टिप्पणी नहीं करने की सलाह देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भविष्य में कब, किसको, किसकी जरूरत पड़ जाए, यह कहा नहीं जा सकता। मायावती ने यहां एक बयान में किसी का नाम लिये बगैर कहा, विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं उनके बारे में किसी का भी फिजूल की टीका—टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वह इससे बचें, क्योंकि भविष्य में, देश में, जनहित में कब किसको, किस की जरूरत पड़ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बसपा प्रमुख ने कहा, टीका—टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े यह ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खासतौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है।

ईडी का समन अवैध और राजनीति से प्रेरित : केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद

केजरीवाल ने गुरुवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने कहा, मैं हर कानूनी सम्मन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हालाँकि, ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह अवैध और राजनीति से प्रेरित है। आप सुप्रीमो ने कहा समन वापस लिया जाना चाहिए। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें 21 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को यह दूसरा समन था।

राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने विपक्षी नेताओं को न्योता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर

बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कई दिग्गज हस्तियों को बुलाया जाएगा वहीं, इन हस्तियों को न्योता भेजा जाना शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के अनुसार कई विपक्षी नेताओं को भी राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। आलोक कुमार के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उद्घाटन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और जद (एस) सुप्रीमो देवेगौड़ा को निमंत्रण भेजा है। नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में राम लला की नई मूर्ति के अभिषेक के लिए कई गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। समारोह की तैयारी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।

भ्रष्टाचार के मामले में तमिलनाडु के मंत्री को तीन वर्ष की सजा

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय के

ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को तीन साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के साथ ही पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और मंत्री पद भी चला गया। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी जयचंद्रन ने पोनमुडी की पत्नी पी. विसालाक्षी को भी तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पोनमुडी और उनकी पत्नी दोनों पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया। उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन सजा गुरुवार को सुनाई। आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन आर एलांगो ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका और सजा निलंबित करने के संबंध में याचिका दाखिल करने की मोहलत दी जाए।

संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 3 और सांसद निलंबित

नईदिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा की बैठक निर्धारित अवधि से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत गत चार दिसंबर को हुई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार 22 दिसंबर तक इसका संचालन होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि इस सत्र में कार्य उत्पादकता करीब 74 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा, ''इस सत्र में 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे 50 मिनट तक चलीं। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए। कुल 18 सरकारी विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए।'' बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लोकसभा की स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन पेश किए।

संसद ने दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दी, 138 साल पुराने कानून की जगह लेगा

देश में 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त कर नया कानून बनाने के लिए लाए गए दूरसंचार विधेयक, 2023 को संसद ने बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र बहुत कठिनाई वाले दौर में था लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में इसे वहां से बाहर लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र पर घोटालों की कालिख लगती थी लेकिन आज यह उदीयमान क्षेत्र बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के कारण दुनिया में सबसे तेज गति से 5जी यहां लागू किया गया और इसके लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया वह भारत में बने हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कई सुधारों को जारी रखा गया है और इसके द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है।

सीईसी, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों एवं सेवा शर्तों से संबंधित विधेयक को संसद की मंजूरी

संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और

निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों एवं उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने से संबंधित एक विधेयक को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी। लोकसभा ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023' को आज ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। राज्य सभा इसे 12 दिसम्बर को पारित कर चुकी है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के एक फैसले को दरकिनार करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, ''यह विधेयक जो हम लाए हैं वह उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नहीं है। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लाया गया है। यह अनुच्छेद 324(2) के तहत सूचीबद्ध प्रावधानों के अनुसार है। यह संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत सूचीबद्ध शक्तियों के पृथक्करण का भी अनुसरण करता है।''

केंद्र सरकार प्रेस की आजादी और मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : ठाकुर

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार प्रेस की आजादी और मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भयमुक्त माहौल मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। ठाकुर उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून पत्रकारों को भी कवर करते हैं। पत्रकारों पर हमले की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि वहां से लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं।

देश के 15 हवाई अड्डों पर 164 विमान निष्क्रिय अवस्था में खड़े हैं : सरकार

देश के 15 हवाई अड्डों पर 164 विमान बेकार खड़े हैं। सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार इनमें से सर्वाधिक विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर निष्क्रिय अवस्था में खड़े हैं जिनकी संख्या 64 है। मंत्री के उत्तर के अनुसार, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 27, मुंबई हवाई अड्डे पर 24 और चेन्नई हवाई अड्डे पर 20 ऐसे विमान खड़े हैं। इनके अलावा अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोचीन, गोवा (मोपा), हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, कन्नूर, नागपुर और रायपुर हवाई अड्डों पर भी बेकार विमान खड़े हैं।

राज्यसभा में गोयल का कांग्रेस पर तंज, कहा कि उन्हें कांग्रेस घास से एलर्जी है

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी दल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस घास से एलर्जी है। 'कांग्रेस घास' विदेशी प्रजाति का एक पौधा है। गोयल ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से यह सवाल किया कि कांग्रेस घास से कैसे एलर्जी होती है? उस समय यादव विदेशी प्रजाति के पौधों के उन्मूलन को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। गोयल ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, जब मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो मुझे कहा गया कि मुझे कांग्रेस घास से एलर्जी है। मैं चाहता हूं कि मंत्री इस बात पर प्रकाश डालें कि कांग्रेस घास से कैसे एलर्जी होती है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मंत्री (यादव) ऐसी जगह से आते हैं जहां यह (पौधा) एक बड़ी चुनौती था। उन्होंने गोयल से कहा, मंत्री को इस बारे में पूरी जानकारी है।

सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का विरोध मार्च

पीएम मोदी संसद छोड़ हर जगह बोलते हैं : खरगे

नईदिल्ली। इस सप्ताह 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली में संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। लोकसभा से 97 और राज्यसभा से 46 सहित निलंबित सांसदों पर 13 दिसंबर को हुए अभूतपूर्व सुरक्षा उल्लंघन पर बहस की मांग के बीच कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इस घटना के दौरान, दो व्यक्ति लोकसभा कक्ष में कूद गए। दर्शक दीर्घा से गैस कनस्तर छोड़े, जिससे संसदीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं।

मार्च के दौरान कांग्रेस सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि सदन में कामकाज हो, राज्यसभा के सभापति एक मुद्दे को उठाने के दौरान संसद में जातिवाद की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि संसद में सुरक्षा चूक मामले को हम उठा रहे थे। हम संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम संसद छोड़कर हर जगह बोलते हैं। हम संसद में सुरक्षा में चूक का मामला उठाना चाहते थे कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। खरगे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही, सदन नहीं चलाना चाहती है। अगर यही है तो अकेले संसद चला लो। पीएम मोदी संसद में बात नहीं करते हैं। निलंबन के जवाब में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है, जिसके बाद अतिरिक्त राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री को सुरक्षा में चूक मामले पर सदन में बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कहीं और बात की लेकिन वह लोकसभा, राज्यसभा में नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें

सुरक्षा चूक मामले पर बोलने दिया जाए, सत्तारूढ़ दल के सांसद कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से 140 सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए गुरुवार को संसद भवन से एक मार्च निकाला जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर हाथों में ले रखा था जिस पर लिखा था 'लोकतंत्र बचाओ'...मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद से जुड़े विषयों पर सदन के बाहर बोल रहे हैं जो विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मीडिया से बात की। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा, हम हमेशा संस्थाओं का सम्मान करते हैं। संसद में जो हुआ वह देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 150 सांसदों को सदन से बाहर करने का ऐतिहासिक काम किया गया है। जिनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि सरकार की ओर से बयान दिया जाए कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं थे वो सदन में कैसे आए। उन्हें पास किसने जारी किया? यह संसद का अधिकार है। मिमिक्री विवाद पर उन्होंने कहा, अगर कोई संसद के बाहर कुछ करता है तो उसे यहां तक ले जाना कि अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ कहता है और मैं कहूं कि यह मराठों और किसानों का अपमान है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा।

खेल
प्रमुख समाचार

पहलवान साक्षी मलिक ने की संन्यास की घोषणा

नईदिल्ली। संजय कुमार सिंह भारतीय कुश्ती

महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वह लम्बे समय तक महासंघ पर राज करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। इस परिणाम के बाद जहां भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने खुशी जताई वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी।

पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। अगर बृजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं...

बजरंग पूनिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अपनी इस बात पर कायम नहीं रही कि बृजभूषण का कोई भी वफादार डब्ल्यूएफआई चुनाव नहीं लड़ेगा। विनेश फोगाट ने भी निराशा जताते हुए कहा कि उभरती हुई महिला पहलवानों को भी अब शोषण झेलना पड़ेगा।

हालांकि पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने कहा, मैं जीत का श्रेय देश के पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के सचिव को देना चाहता हूं...मुझे उम्मीद है कि नई फेडरेशन के गठन के बाद कुश्ती प्रतियोगिताएं फिर से शुरू होंगी।

बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और और भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद वह डब्ल्यूएफआई की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिए गए थे। जब फिर से चुनाव हुए तो खुद बृजभूषण शरण सिंह मैदान में नहीं उतरे लेकिन अपने वफादार संजय कुमार सिंह को चुनाव लड़ाया जिन्होंने जीत हासिल की।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 359 अंक चढ़ा निफ्टी 21,255 पर बंद

नईदिल्ली। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार हरे रंग में लौट आया और उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 350 से ज्यादा अंक की बढ़त लेकर बंद हुआ। शेयर बाजार में 600 अंकों की शुरुआती गिरावट से उबरने के बाद तेजी आई। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 358.79 अंक या 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 70,865.1 0 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 69,920.39 के निचले स्तर तक फिसल गया था। इसी तरह व्यापक एनएसई का निफ्टी-50 भी 108.25 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 21,258.4 पर पहुंच गया। निफ्टी की 38 कंपनियों के शेयर हरे जबकि 12 के शेयर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड के शेयर में सबसे ज्यादा 2.27 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। साथ ही एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, विप्रो, टीसीएस के शेयर में मुख्य रूप में बढ़त के साथ बंद हुए।

कृषि श्रमिकों के लिए इंफ्लेशन रेट नवंबर में बढ़कर 7.37% पर

नईदिल्ली। चावल, गेहूं का आटा, दाल जैसे खाने का समान महंगा होने से कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 7.37 प्रतिशत हो गई। वहीं ग्रामीण श्रमिकों के लिए यह 7.13 प्रतिशत रही। अक्टूबर में कृषि श्रमिकों की खुदरा मुद्रास्फीति 7.08 प्रतिशत और ग्रामीण श्रमिकों की खुदरा मुद्रास्फीति 6.92 प्रतिशत थी। श्रम मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर में क्रमशः 9.38 प्रतिशत और 9.14 प्रतिशत रही, जबकि अक्टूबर, 2023 में यह क्रमशः 8.42 प्रतिशत तथा 8.18 प्रतिशत थी। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर, 2022 में क्रमशः 6.19 प्रतिशत और 6.05 प्रतिशत दर्ज की गई थी। बयान के अनुसार, इस साल नवंबर में कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 12 अंक बढ़कर 1,253 अंक हो गया।

कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष में 1 अरब टन को पार कर जाएगा

नईदिल्ली। कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को विश्वास जताया कि चालू वित्त वर्ष में देश का कोयला उत्पादन एक अरब टन के आंकड़े को पार कर जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का जीवाश्म ईंधन का उत्पादन लक्ष्य 101.21 करोड़ टन है। वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के नौवें दौर के शुभारंभ के दौरान मंत्री ने कहा, ''इस साल हम एक अरब टन उत्पादन स्तर को पार करने जा रहे हैं।'' चालू वित्त वर्ष में कोयले की अनुमानित मांग 119.66 करोड़ टन है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक बिजली की मांग दोगुनी होने वाली है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए देश को कोयले की जरूरत है। नौवें दौर की नीलामी पूरी होने के साथ ही 100 कोयला ब्लॉकों की बिक्री पूरी हो जायेगी। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के नौवें दौर में कुल 31 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। ये खदानें कोयला, लिग्नाइट वाले राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हैं।

शेयर बाजार में आईनॉक्स इंडिया का आईपीओ लिस्ट

नईदिल्ली।

क्रायोजेनिक टैंक बनाने वाली आईनॉक्स इंडिया के आईपीओ आज शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हो गई है। कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस 660 रुपये से 44 फीसदी उछाल के साथ बाजार में लिस्ट हुए। बीएसई पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 41.38 फीसदी चढ़कर 933.15 रुपये पर शुरुआत की। बाद में 48.31 प्रतिशत के उछाल के साथ 978.90 रुपये पर पहुंच गए। एनएसई पर शेयर 43.88 प्रतिशत की तेजी के साथ 949.65 रुपये पर लिस्ट हुए। कंपनी का बाजार मूल्यांकन शुरुआती कारोबार में 8,522.24 करोड़ रुपये रहा। आईनॉक्स इंडिया का आईपीओ साइज 1459.32 करोड़ रुपये है। यह सब्सक्रिप्शन के लिए 14 से 18 दिसंबर के बीच खुला था। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 19 दिसंबर को हुआ।

शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के मायने

अभिजीत मुखोपाध्याय

इस वर्ष समूची दुनिया के शेयर बाजारों में तेजी देखी गयी है। वित्तीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शेयर बाजारों के लिहाज से यह बहुत अच्छा साल रहा है। साल के आखिरी महीनों में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। गंभीर आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यूरोपीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा है। यह बड़े अचरज की बात है कि जापानी शेयर बाजार, जो कई वर्षों से अच्छा नहीं कर रहा था, में इस साल बड़ी उछाल देखी गयी। साल 1989-90 के बाद जापान का शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर है। भारतीय स्टॉक मार्केट भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसइ) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसइ) ऐतिहासिक स्तर पर हैं। शेयर बाजारों के मामले में इस साल का सबसे बड़ा अपवाद चीन रहा है। हाल के समय में दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि कम हुई है और उससे उबरने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। चीन के प्रॉपर्टी बाजार (रियल एस्टेट सेक्टर) में उतार-चढ़ाव को लेकर व्यापक रूप से अंदेशा जताया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, हांगकांग स्टॉक मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसके बाजार मूल्य में कमी आयी है। उल्लेखनीय है कि मूल्य की दृष्टि से भारतीय स्टॉक मार्केट ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय शेयर बाजार अभी दुनिया का सातवां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है।

दुनियाभर के बाजारों में तेजी का संबंध निकट भविष्य को लेकर सकारात्मक अपेक्षाओं से है। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मुद्रास्फीति में गिरावट आयी है। आम तौर पर यह माना जा

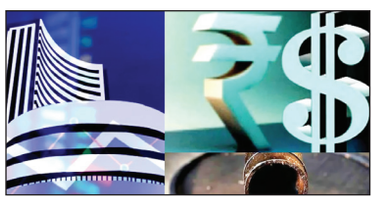

रहा है कि अगले वर्ष मुद्रास्फीति में और भी कमी आयेगी। उल्लेखनीय है कि वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ाने में कोरोना महामारी तथा रूस-यूक्रेन युद्ध की बड़ी भूमिका रही है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आने से उम्मीद की जा रही है कि दुनियाभर के केंद्रीय बैंक या तो ब्याज दरों में कमी करेंगे या कम से कम उनमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इससे यह अपेक्षा बनी है कि बाजार में पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि होगी। यह जो अतिरिक्त पैसा आयेगा, वह विश्व के बड़े हिस्से में आर्थिक वृद्धि को भी गति देगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था पर दबाव में कमी आयेगी।

विशेष रूप भारतीय शेयर बाजार में इस साल लगातार रिकॉर्ड बढ़त होती रही है। इस कारण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। बीएसइ के सेंसेक्स और निफ्टी सूचकांक लगातार अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं। कुल मिला कर, इस साल अब तक भारतीय स्टॉक मार्केट में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर के अंत तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कुल बाजार पूंजी 3.989 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी थी। भारतीय शेयर बाजार में इस शानदार उछाल के कुछ मुख्य कारण हैं। निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि से संबंधित उम्मीदें इन कारणों में एक है। वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आरंभिक आकलनों में आर्थिक वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही, जो पूर्ववर्ती अनुमानों से अधिक है। मार्च 2024 में समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर के 6.4 प्रतिशत के आसपास रहने की आशा है। अगर इस दर को हासिल कर लिया जाता है, तो यह छह प्रतिशत के पूर्ववर्ती अनुमान से अधिक होगा। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि को लेकर बनी मौजूदा उम्मीदें भारत के वित्तीय बाजारों को एक वांछनीय गंतव्य बना रही हैं। एचएसबीसी के पूर्वानुमानों के अनुसार, अगले वर्ष भारतीय शेयर बाजारों में कमाई में बढ़ोतरी 17.8 प्रतिशत के आसपास रहेगी। यह एशिया में सबसे अधिक दरों में एक है। बेहतर कमाई की यह संभावना बाजार में पैसा भी ला रही है। माना जा रहा है कि बैंक, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जो अगले साल स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाल के समय में भारतीय शेयर बाजार में घरेलू भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छोटे या खुदरा निवेशक बड़ी संख्या में बाजार से जुड़े हैं और यह प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर भारत सरकार ने दी तत्काल अनुमति

सेन्ट्रल पूल में छग से 15 लाख मेट्रिक टन

उसना चावल लेगा एफसीआई

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आग्रह को भारत सरकार ने तत्काल स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ से सेन्ट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ से उसना चावल उपार्जित किए जाने की अनुमति काफी दिनों से लंबित थी। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से उसना चावल के उपार्जन की अनुमति मिलने पर कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से राज्य को यह फायदा मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल का इसके लिए राज्य की ओर से आभार जताया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की स्थिति एवं कस्टम मिलिंग की ओर केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल का ध्यान आकर्षित करते हुए 21 दिसंबर को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में सेन्ट्रल पूल में चावल उपार्जन का कोटा 61 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 74 लाख मेट्रिक टन करने के साथ ही राज्य से

59 लाख मेट्रिक टन अरवा तथा 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लिए जाने का अनुरोध अपने पत्र में किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 दिसंबर की स्थिति में समर्थन मूल्य पर 8.68 लाख किसानों से 39.63 लाख मेट्रिक टन

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि

धान का उपार्जन किया जा चुका है एवं प्रतिदिन 3 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान की आवक हो रही है। इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 130 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है। जिसके कस्टम मिलिंग से 88 लाख मेट्रिक टन चावल निर्मित होगा। इसमें से केन्द्रीय पूल में लगभग 74 लाख मेट्रिक टन (भारतीय खाद्य निगम में 58 मेट्रिक लाख टन एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 16 लाख टन) एवं स्टेट पूल में 14 लाख टन चावल का उपार्जन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश हेतु केन्द्रीय पूल में 61 लाख टन चावल उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में कुछ किस्म के धान के मिलिंग में ज्यादा ब्रोकन आने के कारण निर्धारित गुणवत्ता का अरवा चावल नहीं बनने से अरवा मिलिंग में कठिनाईयां आती है। ऐसे धान की उसना मिलिंग कराने से कस्टम मिलिंग में गति आयेगी। मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्री के निर्देश पर भारत सरकार के खाद्य विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ से 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल उपार्जन की स्वीकृति का पत्र जारी कर दिया गया है।

किसानों को दो साल का बोनस मिलेगा 25 को

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर बोनस राशि वितरण की तैयारियां शुरू

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति तथा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3100 रूपए में खरीदी के वादे पर अमल के बाद अब किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किए जाने की तैयारी जोरों से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर हम राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे।

गौरतलब है कि मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के किसानों को दो वर्ष के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने राज्य के किसानों से किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई है।

कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत किसानों से उक्त दोनों वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के एवज में प्रति क्विंटल के मान से 300 रूपए की दर से बोनस (धान उपार्जन प्रोत्साहन योजना) का भुगतान किया जाएगा। बोनस राशि के भुगतान का कार्यक्रम राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर पर 25 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान भाईयों से संवाद करेंगे। विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों द्वारा हितग्राही किसानों को धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

किसानों से प्रति एकड़ 21 क्वि. धान खरीदेगी सरकार

धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा इसका लाभ

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के किसानों से किए गये वायदे के अनुसार राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादे को पूरा करेगी। हम राज्य के किसानों से 3100 रूपए क्विंटल के मान से धान की खरीदी करेंगे। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के एवज में किसानों को लगभग 40 हजार करोड़ का भुगतान होगा। गौरतलब है कि राज्य में अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है। धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से होने पर किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय पर लगभग 23,355 रूपए का अधिक लाभ मिलेगा। पिछली सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी और चार किश्तों में इनपुट सब्सिडी के कुल भुगतान को मिलाकर अधिकतम 41,745 रूपए का भुगतान किया जा रहा था। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को लागू करके किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। इससे किसानों को प्रति एकड़ का धान बेचने पर कुल 65,100 रूपए का भुगतान होगा, जो उन्हें धान खरीदी के एवज में अब तक हो रहे भुगतान से 23,355 रूपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी खरीदी केन्द्रों में बेहतर और पर्याप्त इंतजाम किए जाने के भी निर्देश दिए गये हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल लिंकिग के साथ होगी।

बाबू भैया की कलम से

अनुपूरकः वादों को पूरा करने उठे कदम

छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही राजनैतिक परिदृश्य धीरे धीरे अपने नए आकार में प्रवेश कर रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री,विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष तीनों ही एक मिजाज के दिखे। विष्णुदेव साय,डॉ.रमन सिंह व चरणदास महंत को लोग सौम्य,सरल-सहज नेता मानते हैं। तीनों के बीच की इस समानता को छत्तीसगढ़ की विधानसभा व सरकार व विपक्ष के तालमेल के माध्यम से जनता प्रदेश के समुचित विकास व उत्थान के दृष्टिकोण से देख रही है। सदन में तीनों के इस समान गुण की अनेक लोगों ने अच्छे शब्दों में व्याख्या की। सभी का लब्बो लुआब भी यही दिखा कि तीनों मिल कर पक्ष विपक्ष में भेदभाव से परे प्रदेश के विकास को अंजाम देंगें। लोगों की यह सोच तो अच्छी है लेकिन राजनीति ऐसा होने देगी क्या ? यह बड़ा प्रश्न है। जोगी से लेकर डॉ.रमनसिंह के 15 साल के शासन के रास्ते भूपेश सरकार ने भी अपना कमोबेश योगदान इस प्रदेश को दिया है। भले ही ये कहा जा सकता है कि अपने- अपने तरीके से किया है। जहां स्व.अजित जोगी ने धान खरीदी की सरकारी प्रथा शुरू की जो आज प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना बनी हुई है और किसानों गरीबों के पेट से जुड़ी है। गरीब किसानों के लिए जीवनाधार बनी हुई है। हर साल सरकार की तरफ किसान देखता है। उम्मीदें लगाता है और सरकारें उसकी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। डॉ.रमनसिंह की सरकार ने 15 सालों में अपने तरीके से इस योजना को परिपक्व तथा पारदर्शी बनाने कड़ी मेहनत की। साथ ही प्रदेश के बिगड़े अधोसंरचनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए इतना काम 15 सालों में कर दिया कि अगली सरकार के लिए इस क्षेत्र में नया कुछ करने को खास बचा नहीं। भूपेश सरकार आई उसने अपना प्रदेश सेवा का नया पैमाना बनाया। गांव गरीब को प्राथमिकता में रखा किसान को महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिकता प्रदान की , पहले ही दिन से कर्ज माफ का वायदा पूरा करने के साथ जो भी योजना बनाई उसमें गांव की सेवा का संकल्प ज्यादा दिखा। जमीनी स्तर पर छोटी छोटी योजनाओं को लागू किया,जिसका लाभ गरीबों में निहित था। चुनाव में उन्हें इसी सेवा का लाभ मिलने की पूरी संभावना थी पर यह संभव नहीं हो पाया। जनता ने सरकार की संभावनाओं को एकदम उल्टा कर दिया यह जनता जनार्दन है कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता। यह कहने के सिवाय कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। अब नई उम्मीदों के साथ विपक्ष में बैठने के सिवाय रास्ता नहीं है। कांग्रेस ने अपने विधायक दल का नेता डॉ.चरणदास महंत को बना कर कार्यकर्ताओं को नया संदेश देने का प्रयास किया है,वहीं भूपेश बघेल का ओहदा भी राष्ट्रीय बनाते हुए उन्हें बड़ा काम सौंप दिया है। कांग्रेस के पास भले ही अभी कहने के लिए कुछ ना हो लेकिन भाजपा की नई सरकार का चेहरा साफ होने के बाद उसके कदमों से दिशा दशा का संकेत मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस की भूमिका भी तय हो जाएगी। भाजपा का कहना था कि 2018 में अपनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के माध्यम से कांग्रेस सरकार में आई थी। बाद में उसकी दिशा दशा बदल गई थी। अब भाजपा ने भी बड़ी बड़ी घोषणाओं को मोदी की गारंटी में शामिल किया है। उसे पूरा करने के बाद ही दिशा-दशा साफ हो जाएगी। कांग्रेस यह मान कर चल रही है कि भाजपा ने झूठ के बल पर घोषणाएं की हैं उसे पूरा नहीं कर पायेगी। यहीं से कांग्रेस के विपक्ष की भूमिका तैयार होगी। उम्मीद कितनी पूरी होती है और कितनी नहीं यह तो अभी नई सरकार की चालों से आगे समझ में आएगा।

फिलहाल पहली केबिनेट में विष्णुदेव साय ने गरीबों को आवास योजना की घोषणा पर अमल करते हुए निर्णय ले लिया है। कांग्रेस की नजर अब उसके क्रियान्यवन की ओर लगेंगी। आवास आवंटन में उसकी मॉनिटरिंग होगी। मुख्यमंत्री पर अन्य योजनाओं के क्रियान्यवन का दबाव बनाने का प्रयास भी कांग्रेस कर रही है। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट अनुमान प्रस्तुत हुआ है उसमें भाजपा की सरकार ने महतारी वंदन योजना को अमली जामा इसी माह से पहुंचाने के लिए राशि का प्रावधान करके तथा पिछले दो वर्षों की धान की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान करके अपनी सरकार की प्राथमिकता दर्शाने का काम किया है। नई धान खरीदी की प्रोत्साहन राशि पर कोई बात नहीं की है। चल रही धान खरीदी की राशि 3100 व 21 क्विंटल वाली बात निकट भविष्य में कांग्रेस जोरों से उठाएगी इसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। यह तो कहा ही जा सकता है कि खाली खजाने के बीच महतारी वंदन योजना को आगे बढाने व दो साल की प्रोत्साहन राशि देने की ओर अनुपूरक बजट में प्रावधान करके भाजपा की नई सरकार ने अपना संकल्प जाहिर करने का अच्छा प्रयास किया है लेकिन अभी वर्तमान धान खरीदी में अपने वायदे को पूरा करने का दबाव भाजपा सरकार पर रहेगा। मंत्रिमंडल का गठन पूरा होने के बाद भी काफी कुछ समझ में आने लगेगा कि पक्ष व विपक्ष की दशा व दिशा क्या होने वाली है। घोषणाओं से लाभान्वित होने वालों में इसकी प्रतीक्षा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भूपेश ने अनुपूरक बजट को बताया 'ऊंट के मुंह में जीरा'

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि अनुपूरक बजट से सभी वर्गों को निराशा हुई है. यह अनुपूरक बजट ऊंट के मुंह में जीरा है. इसके साथ ही बजट में 3100 में खरीदी की जिक्र नहीं होने के साथ उन्होंने महतारी वंदन योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित बिजली बिल, गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी के अलावा चावल योजना को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा के दौरान कहा कि धान बोनस को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े किया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमारी सरकार को बोनस देने से रोका. केंद्र सरकार ने कहा कि बोनस देंगे तो चावल नहीं लेंगे. मैंने केंद्र सरकार से बोनस पर रोक हटाने की मांग की थी. भारत सरकार ने हमारे रहते रोक नहीं हटाई थी. भूपेश बघेल ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है, आपको फोन से आदेश मिल जाएगा. लेकिन आदेश के बगैर आप बोनस का वितरण नहीं कर पाएंगे. भाजपा के घोषणापत्र में धान किसानों को 3100 देने की बात है, बाकी किसानों के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है. बोनस को लेकर ही आपने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन 3100 में खरीदी के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है. कांग्रेस विधायक ने महतारी वंदन योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के दायरे में कौन आएगा स्पष्ट हो. गैस सिलेंडर के लिए कौन-कौन पात्र हैं, यह भी स्पष्ट करें.

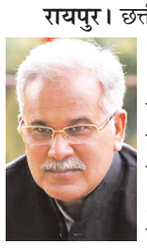

पीएम आवास के लिए केवल 3799 करोड़ का प्रावधान करके 18 लाख आवास बनाने का दावा जनता से दगाबाजी है

रायपुर। जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार हर साल, 100 दिन में महंगाई कम करने और हर खाते में 15-15 लाख रुपए आने का वादा जुमला साबित हुआ, उसी तरह से विधानसभा चुनाव के मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए दावे भी जुमले साबित हुए हैं। पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने विगत बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। मुख्यमंत्री और भाजपा बताये 18 लाख आवास किनके लिये बना रहे उनकी सूची सार्वजनिक किया जाये। अनुपूरक बजट में पीएम आवास के लिए सिर्फ 3799 करोड़ का प्रावधान है इतनी राशि में 18 लाख आवास कैसे बनेगा इसका जवाब भाजपा दे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि 18 लाख पीएम आवास के लिए राज्यांश की राशि कितनी होती है रु. 3799 करोड़ अनुपूरक बजट में स्वीकृत की गई है।

लोकतंत्र को कुचलने वाले सुचिता की बात करते हैं

रायपुर। महिला आयोग अध्यक्ष पद पर रंजना साहू के सुचिता वाले बयान पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के प्रवक्ता कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाया है और कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जुलाई 2026 तक महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक रहेंगी। राजपूत ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता रंजना साहू को बयान जारी करने से पहले उन्हें नैतिकता के नाते कुछ विधि का ज्ञान रखना था क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इसी आयोग में एक माननीय सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी किरण ने अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था उसी तरह से बाल आयोग के अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया था, पिछड़ा वर्ग में भी अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा किया था तब उन्हें राजनीतिक सुचिता का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया गया ऐसे अनगिनत उदाहरण है। भाजपा प्रवक्ता को पहले अपने पार्टी के नेताओं को सुचिता का पाठ पढना चाहिए। उन्होंने इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्य का हनन एक बार नहीं कई बार किया है बार-बार किया है। संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों का कांग्रेस ने हमेशा आदर किया है। भाजपा सरकार को और भाजपा प्रवक्ताओं को अगर कोर्ट के आदेश से कोई तकलीफ है तो सार्वजनिक बयान बाजी करने से अच्छा है अपनी बातों को न्यायालय जाकर न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए।

सड़क पर कब्जा रोकने चूना मार्किंग

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा अवैध रूप से संचालित दुकानों एवं सड़क पर यातायात बाधित करने वाले ठेलों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही वहां दोबारा कब्जा ना हो जाये इसे सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये है। निगम के अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय ने बताया कि व्यस्ततम बाजार एवं मार्गो पर जहां बाजार एवं व्यवसायिक गतिविधियों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। ऐसे 18 स्थानों पर चूना मार्किंग की गई है। जिसके बाहर किसी प्रकार का सामान रखने या अवैध रूप से पार्किंग की जायेगी तो सामान या वाहन को यातायात विभाग एवं निगम द्वारा जप्ती की कार्यवाही की जायेगी। अभी तक अवैध रूप से संचालित दुकानों एवं सड़कों पर यातायात बाधित करने वाले ठेलो को हटाते हुए लगभग 2 लाख 80 हजार वर्गफीट सड़क और जमीन को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। साथ ही समस्त जोन कमिश्नरों को उक्त कब्जा मुक्त क्षेत्र में दोबारा कब्जा ना हो इसके लिए लगातार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये है।

बीजापुर में नक्सलियों ने दो बसों पर लगाई आग, पत्रकारों पर सीआरपीएफ के जवानों ने किया दुर्व्यवहार

बीजापुर. नक्सलियों ने बीजापुर और आवापल्ली के बीच दो यात्री बसों को आग के हवाले कर दिया. इस घटना की कवरेज कर वापस लौटते वक्त पत्रकारों पर सीआरपीएफ के जवानों ने बंदूक तानी. साथ ही दुर्व्यवहार भी किया. जवानों की इस करतूत से पत्रकारों में आक्रोश है. बता दें कि भारत बंद के एक दिन पहले नक्सलियों ने बीजापुर और आवापल्ली के बीच दो यात्री बस को आग के हवाले कर दिया. रॉयल ट्रेवल्स की बस से सभी यात्रियों को उतारकर ड्राइवर की पिटाई करने के बाद बस को आग के हवाले किया. रॉयल ट्रेवल्स की बस आवापल्ली से बीजापुर होते हुए रायपुर आ रही थी, तभी नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया. माओवादियों द्वारा जमकर मचाए गए उत्पात की रिपोर्टिंग कर 5 पत्रकारों का दल वापस लौट रहा था. इस दौरान मुर्किनार सीआरपीएफ कैंप में वेरिफाई करने के नाम पर जवानों ने पत्रकारों से बदसलूकी की. जवानों की इस करतूत से पत्रकारों में आक्रोश है और इस घटना की निंदा भी की है.

गिरीश पंकज का व्यंग्य नाटक कनाडा में मंचित

सौ से अधिक पुस्तकों के रचयिता व्यंग्यकार गिरीश पंकज द्वारा लिखित व्यंग्य नाटक 'देश की पुकार' का सात समंदर पार कनाडा में मंचन किया गया। स्प्रिंगडेल ब्रांच लाइब्रेरी,ब्रेम्पटन में आयोजित कार्यक्रम में हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा श्रुति-नाटक के रूप में नाटक मंचित किया। गिल्ड ने मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर और धर्मवीर भारती की रचनाओं का भी मंचन किया। श्रुति नाटक में कलाकार मंच पर आकर

पटकथा को देखते हुए संवाद अदा करते हैं। नाटक का निर्देशन सुश्री कृष्णा वर्मा ने किया। विभिन्न पात्रों की भूमिका नरेंद्र ग्रोवर (बूढ़ा आदमी), संदीप कुमार, दीपक राजदान (युवक), कृष्णा वर्मा (युवती),पीयूष श्रीवास्तव (सूत्रधार, नेता), सुरेश पांडे (नेता), नवीन पांडे (कवि) एवं विद्याभूषण धर (तरुण) ने निभाई। नाटक का सार यह है कि एक गड्ढे में एक बुजुर्ग व्यक्ति गिर जाता है। जिसका नाम है देश कुमार। रास्ते से गुजरने वाला वाले नेता, युवक, यवती आदि उसे बाहर नहीं निकालते। अंत में एक बच्चा हाथ बढ़ाता है और बुजुर्ग गड्ढे से बाहर आ जाता है।

योगेश ममगई के कुशल संचालन ने अंत तक श्रोताओं को बाँधे रखा। धर्मवीर भारती की 'कनुप्रिया' पर शास्त्रीय नृत्य नाटिका प्रस्तुत की आशना सक्सेना ने। रामधारी सिंह दिनकर की 'रश्मिरथी' के 'कृष्ण- कर्ण संवाद' में कृष्ण की भूमिका निभाई पीयूष श्रीवास्तव, कर्ण की संदीप सिंह और सूत्रधार की विद्याभूषण धर ने।

मैथिलीशरण गुप्त के 'यशोधरा' की नाट्य अभिव्यक्ति की शैलजा सक्सेना और मानोशी चटर्जी ने।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टोरोंटो कौंसलावास के चांसरी प्रमुख, संजीव सकलानी थे। कृष्णा वर्मा ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।कार्यक्रम का शुभारंभ मानोशी चटर्जी के सरस्वती वंदना से हुआ। तरुण मंच से अविका सिंह नौ वर्षीय श्लोक सिंह ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। कविता सहाय ने मीरा बाई के दो सुंदर भजन प्रस्तुत किए। अपनी लघुकथा 'अधिकार' का वाचन किया प्रीति अग्रवाल ने।

कार्यक्रम की परियोजना डॉ. शैलजा सक्सेना, और संयोजन पूनमचंद्रा मनु का था। अंत में विजय विक्रांत ने धन्यवाद किया।

किसान क्रेडिट कार्ड से लिया ऋण, दूध के व्यवसाय से बदली किस्मत

रायपुर। पशुधन किसानों और उनकी आजीविका का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गायों का पालन एक किफायती और टिकाऊ पेशा हो सकता है, इसके उदाहरण है रायपुर जिले के शंकर यादव। पहले वह एक मजदूर थे और उन्हें आय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पशुधन विकास विभाग के सहयोग से आज वह एक सफल डेयरी किसान बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जब शंकर ने ''मेरी कहानी मेरी जबानी'' के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी लोगों को बताई तो शिविर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

रायपुर के तिल्दा ब्लॉक के तामासीवनी गांव में रहने वाले शंकर यादव ने केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाकर दूध का व्यवसाय शुरु कर आर्थिक सफलता हासिल की।

शंकर गांव के एक सामान्य परिवार में रहते है जहां उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। पहले उनके पास कुछ नहीं था और आय के लिए वह मजदूरी करते थे पर इससे उनकी आमदनी इतनी नही हो पाती थी की वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए वह दुग्ध सहकारी संघ में मजदूरी करने लगे और संघ में दूध पहुंचाने का काम शुरु किया। उन्हें वहां पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस काम के साथ वह अपना व्यवसाय भी शुरु कर और आर्थिक रुप से सशक्त हो सकते हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.